वर्ष 12 • अंक 290 • 12+8 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 23 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

बिजली दर घटीं, चीनी मिलों पर दबाव

शशि शंकर ▶▶ पृष्ठ 3

बदलते ऊर्जा परिदृश्य में भी दिख रहीं बड़ी संभावनाएं

डॉलर रु. 71.20 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 78.90 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39916 ▲ 62 रुपये | सेंसेक्स 41115.40 ▼ 208.40 | निफ्टी 12106.90 ▼ 62.90 | निफ्टी फ्यूचर्स 12145.30 ▲ 38.30 | ब्रेंट क्रूड 63.70 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

बजट के दिन शनिवार को खुला रहेगा शेयर बाजार

शेयर बाजार शनिवार 1 फरवरी को बजट के दिन खुले रहेंगे और इनमें सामान्य कामकाज होगा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। आम तौर पर बजट के दिन बाजार में खासा उतार-चढ़ाव रहता है क्योंकि निवेशक बजट के प्रावधानों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर प्रतिक्रिया देते हैं। पिछली बार 2015 में शनिवार के दिन बजट पेश किया गया था।

जीएसटीआर-3बी के लिए अलग-अलग अंतिम तिथि

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर के तहत मासिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी भरने की तिथि अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से तीन तारीख में बांटने का निर्णय किया है। इस कदम का मकसद सिस्टम पर दबाव कम करना है। वर्तमान में हर महीने की 20 तारीख को जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि होती है। लेकिन अब विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिए अंतिम तिथि हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख होगी। जीएसटी नेटवर्क के सिस्टम में रिटर्न भरने के दौरान दिक्कतों को देखते हुए ऐसा किया गया है। करीब 20 फीसदी जीएसटीआर-3बी रिटर्न अंतिम तिथि को भरे जाते हैं।

आईटीआई के एफपीओ का मूल्य दायरा 72 से 77 रुपये

सार्वजनिक क्षेत्र की तकनीकी कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने अपने एफपीओ निर्गम का मूल्य दायरा 72 से 77 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का शेयर 99.8 रुपये पर बंद हुआ था। ऐसे में उच्च मूल्य दायरे पर बंद भाव की तुलना में 23 फीसदी और निचले दायरे में 28 फीसदी छूट दी जा रही है। बाजार के भागीदारों का कहना है कि छूट का दायरा कम हो सकता है क्योंकि मौजूदा निवेशक शेयर बेच सकते हैं और फिर एफपीओ में उसे खरीद सकते हैं। निर्गम के उच्च मूल्य पर कंपनी 1,386 करोड़ रुपये जुटा सकती है। एफपीओ शुक्रवार को खुलेगा और मंगलवार को बंद होगा।

सीएए पर रोक से इनकार केंद्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि वह केंद्र का पक्ष सुने बगैर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर रोक नहीं लगाएगा। न्यायालय ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का वक्त दिया और कहा कि इस मामले की सुनवाई पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली 143 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालयों को इस मामले पर फैसला होने तक सीएए को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से रोक दिया।

9000 से अधिक यात्रियों की जांच, नहीं मिला संक्रमण

चीन में कोरोना वायरस फैलने से भारत भी सतर्क हो गया है। केंद्रीय वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बुधवार को बताया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत सात चिह्नित हवाई अड्डों पर मंगलवार तक कुल 43 उड़ानों और 9,156 यात्रियों की नए तरह के कोरोना वायरस के लिए जांच की गई। उन्होंने बताया कि अभी तक जांच में कोई मामला सामने नहीं आया है। पृष्ठ 12

व्यापार गोष्ठी

आपकी राय में कैसा हो आम बजट?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्यों पर बढ़ेगा दबाव

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या दूरसंचार कंपनियों को मिलनी चाहिए भुगतान से राहत?	हां	63.64%
	नहीं	36.36%

करों में घटेगा राज्यों का हिस्सा!

वित्त आयोग केंद्रीय करों में घटा सकता है राज्यों का हिस्सा, बढ़ सकता है अनुदान

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 22 जनवरी

15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 की अपनी रिपोर्ट में संभवत: केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 42 फीसदी से कम करने की सिफारिश की है। इससे राजस्व की कमी से जूझ रहे केंद्र को कुछ राहत मिलेगी। बिज़नेस स्टैंडर्ड को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आयोग ने उनके राजस्व घाटे और आपदा अनुदान की राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया है। साथ ही राज्यों को फिर से प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने का भी सुझाव दिया गया है।

एनके सिंह की अगुआई वाले 15वें वित्त आयोग ने दिसंबर में अपनी पहली रिपोर्ट राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को सौंपी थी। वित्त मंत्रालय बजट सत्र में आम बजट से पहले इसे संसद में पेश कर सकती है। वित्त मंत्रालय इस इस रिपोर्ट के साथ कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करेगा। इनमें 15वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों की जानकारी दी जाएगी जिन्होंने केंद्र ने स्वीकार कर लिया है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में संतुलन बनाने की कोशिश की है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कम कर दिया गया है, लेकिन उनके लिए अनुदान बढ़ा दिया गया है।' अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त फंड शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान और आपदा राहत के रूप में होगा। इस फंड का कुछ हिस्सा विभिन्न मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन से भी जुड़ा होगा। इनमें ये मानक भी होंगे कि ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और बुनियादी क्षेत्र की नीतियों पर उनका प्रदर्शन कैसा रहा।

15वें वित्त आयोग का रुख 14वें वित्त आयोग के उलट है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, '14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया था लेकिन राज्यों का अनुदान कम कर दिया था।'

यह देखना होगा कि केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में कितनी कटौती की गई है और राज्यों के अनुदान में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यानी केंद्र या राज्यों पर इसका क्या असर होता है। केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्यों के बीच पहले से ही नागरिकता संशोधन कानून सहित कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। इसके मद्देनजर केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में कटौती से केंद्र और राज्यों के रिश्ते और बदतर हो सकते हैं।

केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में कमी निश्चित रूप से केंद्र सरकार के लिए अच्छी खबर होगी। आर्थिक सुस्ती के लंबे समय तक जारी रहने के कारण केंद्र के पास संसाधनों की कमी हो गई है और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस साल सकल राजस्व लक्ष्य में 3.5 लाख करोड़ रुपये तक की कमी हो सकती है। 15वां वित्त आयोग इस साल अक्टूबर में एक और रिपोर्ट सौंपेगा जो वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए होगी। आयोग के कार्यकाल को पिछले साल अक्टूबर में बढ़ाया गया था। इससे उसे अक्टूबर, 2020 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने से पहले विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में योजना बनाने में ज्यादा समय मिलेगा। इनमें आर्थिक सुस्ती, केंद्र और राज्यों के मुश्किल राजकोषीय और राजस्व लक्ष्य, दिल्ली और पुदुच्चेरी जैसे केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में जम्मू कश्मीर की स्थिति शामिल है। आयोग के अध्यक्ष ने साफ किया कि पहली रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को दूसरे केंद्रशासित प्रदेशों के समान माना गया है और इसका फंड केंद्र के हिस्से से आएगा।

- इससे केंद्र को मिलेगी राजस्व के मोर्चे पर राहत
- राज्यों के लिए बढ़ सकती है अनुदान की राशि
- लौट सकती है कि प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की व्यवस्था
- वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट बजट सत्र में होगी पेश

एनके सिंह
चेयरमैन
15वें वित्त आयोग

डेट में बिकवाली कर रहे एफपीआई

बजट से पहले निकाल रहे निवेश

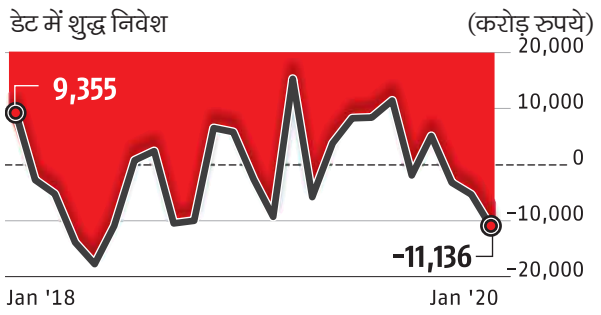

आंकड़े 20 जनवरी, 2020 तक | स्रोत : सेबी/एनएसडीएल | संकलन : बीएस रिसर्च

अनूप रॉय
मुंबई, 22 जनवरी

- बजट में सरकार द्वारा उधारी बढ़ाने के प्रावधान करने की आशंका
- आरबीआई के पास दर में कटौती की गुंजाइश कम रहने का भी बॉन्ड पर असर
- जनवरी में एफपीआई ने 11,136 करोड़ रुपये की बिकवाली की

आम बजट से पहले विदेशी निवेशक डेट, खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश को निकाल रहे हैं। निवेशकों में डर है कि बजट में सरकार भारी-भरकम उधारी लेने का प्रावधान कर सकती है। बॉन्ड बाजार का अनुमान है कि सरकार की उधारी कम से कम 7.5 लाख करोड़ रुपये हो सकती है जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 7 लाख करोड़ रुपये उधारी की योजना बनाई गई थी। इसके साथ ही इस बात की भी आशंका है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास दर में कटौती की गुंजाइश भी कम होगी। दरों में कटौती नहीं होने से प्रतिफल बढ़ सकता है जिससे बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आ सकती है। बॉन्ड डीलरों का कहना है कि इन्हीं आशंकाओं के कारण बजट से पहले निवेशक अपना निवेश निकाल रहे हैं।

जनवरी में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने शुद्ध 1.56 अरब डॉलर की बिकवाली की है। नवंबर में एफपीआई ने 44.2 करोड़ डॉलर का निवेश निकाल लिया था, वहीं दिसंबर में भी 75.6 करोड़ डॉलर की बिकवाली की गई थी। आंकड़ों के अनुसार जनवरी की शुरुआत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सरकारी बॉन्डों में अपनी मंजूर सीमा का 75 फीसदी से अधिक का निवेश किया हुआ था लेकिन मंगलवार को यह घटकर 71 फीसदी रह गया।

10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 6.64 फीसदी पर बंद हुआ, जो दिसंबर में 6.50 प्रतिफल से अधिक है। उस समय आरबीआई ने खुले बाजार में खरीद-बिक्री (ओएमओ) शुरू किया गया था। ओएमओ की घोषणा से पहले बॉन्ड प्रतिफल 6.75 फीसदी तक पहुंच गया था। उसके बाद से आरबीआई ने चार बार विशेष ओएमओ लेकर आया। प्रतिफल में ताजा इजाफा ओएमओ के बावजूद हुआ है जिसे लेकर निवेशक चिंतित हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के प्रमुख ट्रेजरी जयेश मेहता ने कहा, 'बाजार बजट के आंकड़ों पर स्पष्टता का इंतजार कर रहा है और यह भी देखेगा कि आरबीआई की ओर से कितनी मदद मिलती है।' आरबीआई ने दिसंबर में नीतिगत दर को यथावत बनाए रखने से पहले करीब 135 आधार अंक की कटौती कर चुका था। दर में और कमी की गुंजाइश सीमित है। बॉन्ड डीलरों का कहना है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 फीसदी रहने की उम्मीद है जबकि सरकार ने पहले इसे 3.3 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा था। आईसीआईसीआई बैंक में वैश्विक बाजार प्रमुख बी प्रसन्ना ने कहा, 'निवेशक राजकोषीय घाटा बढ़ने और सरकार के उधारी कार्यक्रम पर इसके पड़ने वाले असर से चिंतित हैं। इसके साथ ही मुद्रास्फीति बढ़ने से दरों में नरमी की संभावना भी कम हुई है। ऐसे में एफपीआई डेट में निवेश को लेकर रक्षात्मक रुख अपना रहे हैं।' बॉन्ड बाजार में बिकवाली का यह मतलब नहीं है कि विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में रुचि घट रही है। इक्विटी खंड को लेकर उनका रुख सकारात्मक बना हुआ है। प्रसन्ना ने कहा कि रुपये के हिसाब से देखें तो डेट से 11,136 करोड़ रुपये की निकासी हुई है, वहीं इक्विटी में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

बजट में होंगे विकास बढ़ाने के उपाय

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 22 जनवरी

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को कहा कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कार्ययोजना की घोषणा की जाएगी।

जावडेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट रही है और इसके बारे में किसी को भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाए जाने पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उद्योग को उम्मीद है कि सरकार बजट में आर्थिक विकास को गति देने वाले उपायों की घोषणा करेगी लेकिन सरकार संसाधनों की कमी से जूझ रही है। कर संग्रह और विनिवेश का लक्ष्य 2019-20 के बजट अनुमानों के अनुरूप नहीं चल रहा है।

आधिकारिक अग्रिम अनुमानों के मुताबिक देश की जीडीपी वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में 5 फीसदी रहेगी जो एक दशक में सबसे कम है। पिछले वित्त वर्ष यह 6.8 फीसदी रही थी। अलबत्ता, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था के 4.8 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है।

इससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। आर्थिक मामलों पर भाजपा के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने आईएमएफ के अनुमानों पर संदेह जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'हमें आईएमएफ के अनुमानों पर संदेह है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के प्रभाव पर ध्यान दिया गया है या नहीं। इसमें नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एसएमएसई और एनबीएफसी शामिल है। जीडीपी वृद्धि दर अब अपने खराब दौर से बाहर आ चुकी है और आगे इसमें उल्लेखनीय सुधार होगा।' आईएमएफ ने अगले वर्ष आर्थिक विकास दर के 5.8 फीसदी और वित्त वर्ष 2022 में 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। उसका कहना है कि भारत की आर्थिक विकास दर में सुस्ती के कारण इन दो वर्षों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।

अग्रवाल ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती से प्रभावित हुई है, उन कारणों से नहीं जो आईएमएफ गिना रहा है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया था कि सरकार के मंत्री आईएमएफ और उसकी मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को निशाना बनाएंगे। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि देश की आर्थिक विकास दर आईएमएफ के अनुमान से भी नीचे जा सकती है।

- जावडेकर ने दिए संकेत
- भाजपा ने आईएमएफ के अनुमान पर जताया संदेह
- पार्टी का दावा, पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था

विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे कई कारोबारी नेता

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 22 जनवरी

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ कारोबारी नेता भी ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कारोबारियों की राजनीति करने वाले दो अहम कारोबारी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की राजनीति करने वाले को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में कारोबारी नेता को टिकट देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने विधानसभा चुनाव में कारोबारी नेता को टिकट देने से परहेज किया। लेकिन कारोबारी पृष्ठभूमि के कुछ कारोबारियों को टिकट जरूर दिया है। कारोबारियों के मुताबिक दिल्ली में 20 से 25 लाख कारोबारी मतदाता होने का अनुमान है।

भाजपा ने राजौरी गार्डन विधानसभा से कारोबारी नेता रमेश खन्ना को उम्मीदवार बनाया है। खन्ना अहम कारोबारी संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के दिल्ली प्रभारी हैं। चैंबर ऑफ फ्रूट ऐंड वेजिटेबल आजादपुर के महासचिव और मंडी कारोबारियों की राजनीति करने वाले राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से भाजपा उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार सुमन गुप्ता भी चांदनी चौक के कपड़ा कारोबारी हैं। हालांकि वह किसी कारोबारी संगठन से नहीं जुड़े हैं। कांग्रेस ने रेहड़ी-पटरी कारोबारियों की राजनीति करने वाले अरविंद सिंह को करावल नगर विधानसभा से मैदान में उतारा है। सिंह नैशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। लोकसभा चुनाव में आप व्यापार प्रकोष्ठ और चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री के संयोजक बृजेश गोयल को टिकट देने वाली आप ने विधानसभा चुनाव में किसी कारोबारी नेता को चुनाव में नहीं उतारा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की दिल्ली इकाई के महामंत्री हेमंत गुप्ता ने कहा कि प्रमुख दलों को 10 फीसदी उम्मीदवार कारोबारी नेताओं को बनाना चाहिए था।

- भाजपा ने उतारे दो अहम कारोबारी नेता, कांग्रेस का रेहड़ी-पटरी कारोबारी नेता पर दांव

जलवायु परिवर्तन से जंग को साथ आए दिग्गज

ज्योति मुकुल
नई दिल्ली, 22 जनवरी

जब दुनिया भर के प्रमुख कारोबारी जलवायु परिवर्तन से निपटने की चुनौती को लेकर दावोस में बहस कर रहे हैं उस समय देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर इस चुनौती का सामना करने के इरादे से एक साझा मंच खड़ा कर दिया है। देश के परोपकारी कारोबारियों के सहयोग से तैयार यह मंच न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा बल्कि उसके लिए सभी तरह के संसाधन भी जुटाएगा।

भारतीय जलवायु परिदृश्य में सक्रिय लोगों एवं संगठनों को साथ लाने और उन्हें मजबूती देने के लिए शीर्ष परोपकारी कारोबारियों ने इंडिया क्लाइमेट कलेबरेटिव (आईसीसी) का गठन किया है। इस संस्था से रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, रोहिणी नीलेकणी, नादिर गोदरेज, अदिति एवं रिशद प्रेमजी, विद्या शाह और हेमेंद्र कोठारी जैसे अग्रणी भारतीय उद्योगपति जुड़े हुए हैं। साझा जलवायु लक्ष्य हासिल करने की दिशा में असरदार कदम उठाना इस सम्मिलित प्रयास का मुख्य उद्देश्य है।

''आईसीसी के जरिये सामूहिक नेतृत्व दुनिया को यह बताता है कि भारत का परोपकारी जगत जलवायु संबंधी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है।''
रतन टाटा

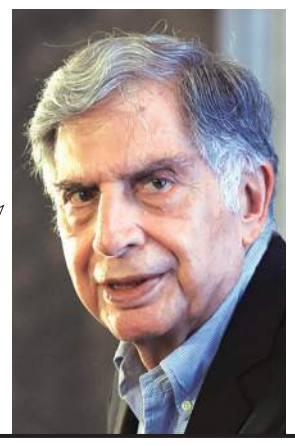

''जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और विकास की राह पर बने रहने के लिए हमें नवाचारी उपायों व बहुआयामी कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा।''
रोहिणी नीलेकणी

आईसीसी ने अपने एक बयान में कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह भारत की जरूरतों को देखते हुए एक केंद्रित एवं बाध्यकारी जलवायु परिप्रेक्ष्य तैयार करेगा जो लोगों की मदद करे और प्रकृति का संवर्द्धन करे।

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा कहते हैं, 'आईसीसी के जरिये हमारा सामूहिक नेतृत्व दुनिया को बताता है कि भारत का परोपकार जगत जलवायु संबंधी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है।' आईसीसी को विविध स्वरों के साथ नवाचारी समाधानों और सामूहिक निवेश का एक सहयोगी मंच बनाने की मंशा है।

टाटा ट्रस्ट्स में संवहनीयता पोर्टफोलियो प्रमुख श्लोका नाथ को नवगठित संस्था का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। श्लोका बताती हैं कि आईसीसी जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर विशुद्ध रूप से भारतीय नजरिये से काम करेगा। उन्होंने कहा, 'अगर हम मिलकर काम करते हैं और जलवायु-अनुकूल बदलाव लाने में लगे लोगों, संगठनों और नीतियों में निवेश करते हैं तो हम अपनी हवा, पानी को साफ कर सकते हैं।'

श्लोका ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि आईसीसी कोई कोष न होकर टेड जैसा एक साझा मंच होगा जो जलवायु परिवर्तन रोकने की पहल में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

ओएनजीसी

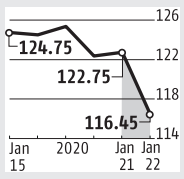

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 122.75 पिछला बंद भाव
₹ 116.45 आज का बंद भाव
▼ 5.13 %

पॉलिकैब इंडिया

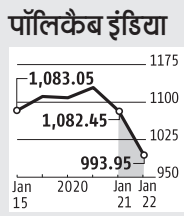

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 1 फीसदी घटा

₹ 1,082.45 पिछला बंद भाव
₹ 993.95 आज का बंद भाव
▼ 8.18 %

इंडियामार्ट इंटरमेश

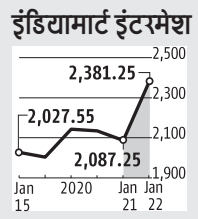

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 36 फीसदी बढ़ा

₹ 2,087.25 पिछला बंद भाव
₹ 2,381.25 आज का बंद भाव
▲ 14.09 %

हैवेल्स इंडिया

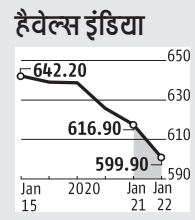

तीसरी तिमाही के दौरान राजस्व 10 फीसदी घटा

₹ 616.90 पिछला बंद भाव
₹ 599.90 आज का बंद भाव
▼ 2.76 %

नेस्ले इंडिया

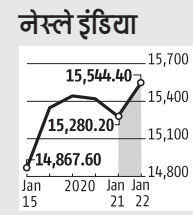

बाजार पूंजीकरण 1.50 लाख करोड़ रुपये के पार

₹ 15,280.20 पिछला बंद भाव
₹ 15,544.40 आज का बंद भाव
▲ 1.73 %

संक्षेप में

टाटा मोटर्स ने प्रीमियम हैचबैक श्रेणी में रखा कदम

टाटा मोटर्स ने बुधवार को अल्ट्रोज को बाजार में उतार कर प्रीमियम हैचबैक श्रेणी में कदम रखा। इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपये है। कंपनी ने अल्ट्रोज के अलावा नेक्सन, टियागो और टिगोर का बीएस-6 संस्करण भी पेश किया है। टाटा मोटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक गुंटर बुश्चेक ने कहा कि कंपनी ने साल की शुरुआत में एक आक्रामक उत्पाद पेश करने का वादा किया था और आज उसे पूरा कर दिया। ईंधन दक्ष, स्वच्छ और टिकाऊ समाधान (वाहन) को हकीकत में बदलना आज की जरूरत है। हमने बीएस-6 इंजन वाले नए पीढ़ी के वाहन को बाजार में उतारकर एक शुरुआत की है। *भाषा*

स्मार्ट ग्रुप वेलनेस सिटी पर करेगा बड़ा निवेश

स्मार्ट ग्रुप दिल्ली में 2025 तक एक वेलनेस सिटी खोलने पर 2,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा। यह दिल्ली के साकेत इलाके में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पास खोली जाएगी। स्मार्ट ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन बीके मोदी ने कहा कि हमारी योजना 2025 तक साकेत में एक वेलनेस सिटी खोलने पर 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की है। यह हमारी 100 साल के बाद तक जिंदगी की अवधारणा के अनुरूप है और इसका मतलब खुशनुमा, स्वस्थ और आजाद जिंदगी से है। इसमें विभिन्न तरह की 1,400 इकाइयां होंगी जिसमें मेडिकल कार्यालय, वेलनेस लिविंग सेंटर, होटल और वेलनेस इलाज केंद्र होंगे। वेलनेस का आशय स्वस्थ जीवन की अवधारणा से है, इसमें व्यायाम, चिकित्सा इत्यादि शामिल है। *भाषा*

दूरसंचार: तय तारीख पर भुगतान नहीं

न्यायालय में संशोधन याचिका पर सुनवाई होने तक इंतजार करेंगी दूरसंचार कंपनियां

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 22 जनवरी

भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड और टाटा समेत प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि वे एजीआर नियमों से जुड़े न्यायालय के आदेश का पालन करेंगी लेकिन वे संबंधित भुगतान करने से पहले उनकी 'संशोधन' याचिका पर शीर्ष न्यायालय में सुनवाई होने के कारण अगले सप्ताह तक इंतजार करेंगी।

इसका अर्थ होगा कि दूरसंचार कंपनियां सरकार को 1,47,000 करोड़ रुपये देने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई 24 जनवरी की तारीख को राशि जमा नहीं कराएंगी। हालांकि तीनों कंपनियों ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारती कल यह पत्र भेजेगी लेकिन दूसरी कंपनियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने बुधवार को ही यह पत्र भेज दिया है या वे गुरुवार को संबंधित पत्र भेजेंगी।

हालांकि रिलायंस जियो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कंपनी गुरुवार को अपने 177 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करेगी और उसने अपने नए वित्तीय परिणामों में संबधित देयता का प्रावधान किया है। जियो न्यायालय में दायर की गई समीक्षा याचिका में पक्षकार नहीं है और उसने इस मुद्दे पर हमेशा अलग रुख रखा।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को बकाया राशि के तौर पर सरकार को 147,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इस आदेश के पुनर्विचार से जुड़ी याचिका सरकार द्वारा खारिज होने के बाद तीन दूरसंचार कंपनियों के इस सप्ताह शीर्ष अदालत में 'संशोधन याचिका' दायर की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने इस याचिका को 'अगले सप्ताह कभी भी' समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने वाले पीठ के सामने सूचीबद्ध करने के लिए सहमति जताई। इसका अर्थ है कि न्यायालय द्वारा भुगतान के लिए तय समयसीमा के निकलने के बाद ही इस पर सुनवाई होगी।

तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में 90 दिनों के भुगतान की समय सीमा में बदलाव के साथ-साथ अपने बकाये के लिए भुगतान की शर्तों और समय पर दूरसंचार विभाग से बातचीत की अनुमति मांगी है। मूल रूप से इसका अर्थ है कि ये कंपनियां किश्तों में भुगतान संबंधी योजना के साथ साथ इसमें कुछ वर्षों की देरी चाहती हैं।

हालांकि दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा था कि अगर दूरसंचार कंपनियां 24 जनवरी तक अपने बकाए का भुगतान नहीं करती हैं तो विभाग को कार्रवाई करनी होगी। वकीलों का कहना है कि भुगतान में चूक होने पर दूरसंचार विभाग कंपनियों की बैंक गारंटी को भुना सकता है। हालांकि गारंटी के तौर पर रखी गई राशि एजीआर बकाये के तौर पर चुकाए जाने वाली 1,47,000 करोड़ रुपये की राशि के बराबर नहीं है जिस स्थिति में विभाग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कि क्यों न उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। कंपनियों को इस नोटिस का जबाव निर्धारित अवधि में देना होगा। सीओएआई के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उद्योग में गंभीर वित्तीय संकट के चलते दूरसंचार विभाग कड़ा रुख नहीं अपनाएगा।

दूरसंचार कंपनियों को सलाह दे रहे वकीलों का कहना है कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि सर्वोचच्च न्यायालय ने पहले के आदेश को निष्पादित नहीं किया क्योंकि उसी अदालत में संबंधित विषय पर दूसरा निर्णय प्रक्रिया में है। उनका मानना है कि इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग से कठोर कार्रवाई करने की उम्मीद नहीं है।

स्पेक्ट्रम बकाया

- दूरसंचार कंपनियों को बकाया राशि के तौर पर सरकार को 147,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है
- जियो गुरुवार को अपने बकाया का भुगतान कर सकती है

ऑयल इंडिया एजीआर बकाये पर अदालत गई

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 22 जनवरी

दूरसंचार विभाग ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को 48,000 करोड़ रुपये एजीआर बकाये का नोटिस भेजा है। कंपनी को यह नोटिस वित्त वर्ष 2008 से वित्त वर्ष 2019 की अवधि के लिए मिला है, जिसमें करीब 48,000 करोड़ रुपये की मांग की गई है और इसमें लाइसेंस शुल्क, जुर्माना और ब्याज शामिल है। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी।

> मूडीज ने कहा, यह भारत के अप्रत्याशित नियामकीय माहौल को प्रतिबिंबित करता है

ऑयल इंडिया इस मामले पर दूरसंचार विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा प्रभावित सीपीएसई से बातचीत कर चुकी है और गैर-दूरसंचार कंपनियों पर एजीआर लागू न होने के बारे में विस्तार से बताया है।

बुधवार को ऑयल इंडिया ने आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण/संशोधन याचिका दाखिल की और अगला कदम याचिका के नतीजे पर आधारित होगा।

मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कहा कि दूरसंचार विभाग की तरफ से बकाए की मांग ओआईएल के लिए नकारात्मक है और यह भारत में अप्रत्याशित नियामकीय माहौल से जुड़े जोखिम को रेखांकित करता है, जहां दूरसंचार व अन्य क्षेत्रों की कई कंपनियों पर कर व लाभांश की मांग का असर पड़ा है क्योंकि सरकार अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

बकाया चुकाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त नकदी नहीं है, कंपनी को भुगतान के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटानी होगी। सितंबर 2019 के आखिर में कंपनी के पास 3,800 करोड़ रुपये नकद थे और मूडीज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2020 में परिचालन से नकदी का प्रवाह करीब 4,000 करोड़ रुपये होगा। दूरसंचार विभाग की मांग कंपनी के वित्त वर्ष 2020 के अनुमानित एबिटा का करीब आठ गुना है और ताजा बाजार पूंजीकरण का करीब तीन गुना।

ऑयल इंडिया ने कंपनी के पाइपलाइन नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन व संरक्षण की खातिर निगरानी व्यवस्था के लिए एनएलडी लाइसेंस हासिल किया था, जिसका इस्तेमाल कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में होता है।

ऐक्सिस बैंक का कर पूर्व लाभ घटा

अभिजित लेले
मुंबई, 22 जनवरी

निजी क्षेत्र के ऐक्सिस बैंक का कर पूर्व लाभ दिसंबर 2019 में समाप्त तिमाही में 8.03 फीसदी की गिरावट के साथ 2,271.77 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 2,470.14 करोड़ रुपये रहा था। बैंक का शेयर आज बीएसई पर 0.7 फीसदी की गिरावट के साथ 712.7 रुपये पर बंद हुआ।

बैंक का शुद्ध लाभ इस अवधि में 4.53 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1,757 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,680.85 करोड़ रुपये रहा था। बैंक को कंपनी कर की दर में कटौती का फायदा मिला। बैंक के लिए कर की प्रभावी दर 33 फीसदी से घटकर 25 फीसदी रह गई।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय तिमाही में 15 फीसदी बढ़कर 6,453 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 5,604 करोड़ रुपये रही थी। शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.57 फीसदी रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 3.36 फीसदी के मुकाबले ज्यादा है। बैंक ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बैंक का गैर-ब्याज राजस्व यानी अन्य आय पांच फीसदी घटकर 4,001 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 3,787 करोड़ रुपये रही थी। बैंक का प्रावधान तीसरी तिमाही में 13.63 फीसदी बढ़कर 3,470 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 3,054.51 करोड़ ररुपये रहा था। सकल एनपीए दिसंबर तिमाही में 5 फीसदी रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 5.75 फीसदी रहा था।

डिजिटल छूट दे रहीं सरकारी तेल विपणन कंपनियां

विश्लेषकों ने कहा, जियो-बीपी की प्रतिस्पर्धा से निपटने की है कवायद

अमृता पिल्लई
मुंबई, 22 जनवरी

तीन सरकारी तेल विपणन कंपनियों में से दो अपने पेट्रोल पंप पर होने वाले डिजिटल लेनदेन के लिए कुछ न कुछ छूट की पेशकश कर रही हैं। खुदरा ईंधन उद्योग के प्रतिनिधि इसे हाल में घोषित जियो-बीपी उपक्रम से मिलने वाली चुनौती से मुकाबले के संकेत के तौर पर देख रहे हैं।

बीपी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एक निश्चित समझौते के अनुसार, 2020 की पहली छमाही में ईंधन के खुदरा कारोबार के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की जाएगी। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा, 'विभिन्न तेल कंपनियां अपने पेट्रोल पंप पर विभिन्न योजनाओं की पेशकश कर रही हैं। इनमें से अधिकतर पेट्रोल पंप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोल पंप आने से सरकारी तेल कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होगी।'

आईओसी से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को 10 फीसदी अथवा 50 रुपये तक कैशबैक की पेशकश कर रही है। यह योजना 1 दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी जो 31 जनवरी तक चलेगी।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंपनी के आउटलेट पर क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी डिजिटल लेनदेन पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी का डिजिटल प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह छूट तत्काल बिल पर दी गई है। इस बाबत जानकारी के लिए एचपीसीएल को भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं आया।

तेल उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नोटबंदी के बाद 2017 में डिजिटल भुगतान पर 0.75 फीसदी का प्रोत्साहन शुरू किया गया था जिसे अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड के लिए बंद कर दिया गया। जबकि अन्य भुगतान के अन्य डिजिटल मोड के लिए यह पेशकश जारी रही।

आरआईएल ने दिसंबर 2019 तिमाही के वित्तीय नतीजे पर अपनी प्रस्तुति में कहा कि कंपनी ने डीजल की बिक्री में 11 फीसदी और पेट्रोल की बिक्री में 15 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि उद्योग के मुकाबले बेहतर रही। समान तिमाही के दौरान उद्योग में डीजल के लिए 0.2 फीसदी और पेट्रोल के लिए 7.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

हालांकि सभी सरकारी तेल विपणन कंपनियां अपने ग्राहकों को समान छूट की पेशकश नहीं कर रही हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम 10 फीसदी तक छूट की पेशकश नहीं कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि समय आने पर कंपनी अपनी कुशलता एवं अन्य उपायों के जरिये जियो-बीपी उद्यम से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना करेगी।

पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि बाजार में मौजूदा सख्ती के मद्देनजर लेनदेन पर छूट देना आसान नहीं होगा। मुंबई पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शिंदे ने कहा, 'डीलर अपने दम पर कोई छूट नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी उपलब्ध कराया जा रहा है वह सीधे तौर पर तेल कंपनियों से दी गई है जो अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाना चाहती है।' देश में पेट्रोल पंप की संख्या जनवरी तक 67,440 थी। इंडियन ऑयल 28,597 पेट्रोल पंपों के साथ बाजार की अग्रणी कंपनी है जबकि उसके बाद एचपीसीएल 16,017 पेट्रोल पंपों के साथ दूसरे पायदान पर है।

डिजिटल लेनदेन

- आईओसी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को 10 फीसदी अथवा 50 रुपये तक कैशबैक की पेशकश कर रही है
- एचपीसीएल अपने आउटलेट पर क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी डिजिटल लेनदेन पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी का डिजिटल प्रोत्साहन दे रही है
- नोटबंदी के बाद 2017 में डिजिटल भुगतान पर 0.75 फीसदी का प्रोत्साहन शुरू किया गया था

बीएस बातचीत

बदलते ऊर्जा परिदृश्य में भी दिख रहीं बड़ी स

घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन और आयातित एलएनजी की ऊंची लागत को झेलने में बाजार की असमर्थता में अंतर के कारण गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने की भारत की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। तेल एवं गैस उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओएनजीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक **शशि शंकर** की **ज्योति मुकुल** से बातचीत के मुख्य अंश:

दो

दुनिया भर में पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में भारत के ऊर्जा परिदृश्य में क्या बदलाव होगा?

पिछले 4 से 5 वर्षों के दौरान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, खासकर तेल एवं गैस कारोबार में काफी उतार-चढ़ाव दिखा है। शेल में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण अमेरिका के तेल एवं गैस में नाटकीय बदलाव आया था जो हमारे कारोबार में प्रौद्योगिकी के महत्त्व को उजागर करता है। लेकिन बाद में उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई और कच्चे तेल की कीमत 26 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क गई। उस दौरान उत्खनन एवं उत्पादन गतिविधियों को तगड़ा झटका लगा और कंपनियां अपने बहीखाते को बचाने के लिए पूंजीगत व्यय एवं खर्च में जबरदस्त कटौती करने ल जब तेल एवं गैस उद्योग में रहा था तो अक्षय ऊर्जा क्षे रफ्तार पकड़ने लगा। वै अक्षय ऊर्जा की ख फीसदी बढ़ी औ औसतन 14 फ गई। लेकिन लघु अ लिह अ

परिणामस्वरूप ऊर्जा में कोयले और तेल की हिस्सेदारी घटेगी। मुझे इस उभरते परिदृश्य में ओएनजीसी के लिए भी काफी संभावनाएं दिख रही हैं।

कच्चे तेल के मुकाबले प्राकृति की भूमिका कितनी र होगी?

स्वच्छ ईंधन के तौर प बढ़ रहा है। हमार ऊर्जा क्षेत्र में गै कुछ वर्षों के का लक्ष में उ है

जरूरत यदि ज

डिफॉल्ट वाली ऋण प्रतिभूतियों में एलआईसी का बड़ा निवेश

सुब्रत पांडा

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने उन इकाइयों की ऋण प्रतिभूतियों में 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है, जिसे रेटिंग एजेंसियों ने डाउनग्रेड कर डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिया है। एलआईसी का यह निवेश विभिन्न प्लेटफॉर्म लाइफ फंड, पेंशन फंड और यूनिट लिंक्ड फंडों के जरिए हुआ है।

ये आंकड़े सितंबर 2019 के आखिर के आंकड़े हैं। एलआईसी के सार्वजनिक डिस्क्लोजर के मुताबिक, सितंबर 2019 के आखिर तक दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड में एलआईसी का 6,120 करोड़ रुपये के निवेश को डाउनग्रेड कर डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिया गया है। इसी तरह सितंबर तिमाही के आखिर तक अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों मसलन रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस होम फाइनैंस आदि में एलआईसी के 7,949.98 करोड़ रुपये के निवेश को डाउनग्रेड कर डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिया गया। एलआईसी के निवेश वाली अन्य ऋण प्रतिभूतियों को भी रेटिंग डाउनग्रेड का झटका लगा, जिनमें एस्सार पावर लिमिटेड, एमटेक ऑटो लिमिटेड, स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड, डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज व अन्य कंपनियां शामिल हैं। डिफॉल्ट वाली इन ऋण प्रतिभूतियों में एलआईसी के लाइफ फंड का निवेश 12,187.57 करोड़ रुपये है, वहीं पेंशन फंड का निवेश 7,741.58 करोड़ रुपये है। इसी तरह यूनिट लिंक्ड फंड का निवेश डिफॉल्ट वाली ऋण प्रतिभूतियों में सितंबर 2019 के आखिर तक 430.08 करोड़ रुपये था।

शीर्ष कंपनियों के डिफॉल्ट ऋण पत्रों में एलआईसी का निवेश

कंपनी का नाम	रकम (करोड़ में)
दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन	6,120
रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	3,399.98
रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड	3,750
रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड	800
जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	1,000
एस्सार पावर लिमिटेड	1,246.72
इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस सर्विसेज	540.5
एमटेक ऑटो लिमिटेड	400
डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड	255

विदेशी निवेश सीमा हटने से एयरटेल को मिलेगा फायदा

भारती एयरटेल में 100 फीसदी विदेशी निवेश की केंद्र सरकार की अनुमति से कंपनी का फायदा कई गुना हो सकता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति में मजबूती के अतिरिक्त सह-प्रवर्तक सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस या सिंगटेल के हक में प्रवर्तक हिस्सेदारी में बदलाव होगा, जिसे निवेशक सकारात्मक मान रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले शेयर 84 फीसदी चढ़ चुका है और बुधवार को यह 11 साल के उच्चस्तर को छू गया।

ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों ने कहा, सिंगटेल अब भारती एयरटेल में बहुलांश हिस्सेदारी चाह सकती है क्योंकि उसकी भारतीय सहायक को 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई है और वह एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। सिंगटेल की एयरटेल में हिस्सेदारी हालिया 2 अरब डॉलर की इक्विटी जुटाए जाने के बाद घटकर 35 फीसदी से नीचे चली गई। *बीएस*

बजट में सब्सिडी सुधार पर ध्यान संभव

राजेश भयानी
मुंबई, 22 जनवरी

राजस्व वसूली कमजोर रहने के मौजूदा दौर में खजाने पर सब्सिडी के अतिरिक्त बोझ को देखते हुए वित्त मंत्रालय सब्सिडी में सुधार पर विचार कर रहा है। मुख्य ध्यान खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी पर है। बहरहाल किसानों को भरपाई के इन दोनों तरह की सब्सिडी के अन्य वैकल्पिक साधन जटिल हैं और उनके प्रशासन से जुड़े तमाम मसले भी हैं।

सूत्रों के मुताबिक अब यह प्रस्ताव है कि दोनों तरह की सब्सिडी का किसानों को सीधे हस्तांतरण किया जाए। लेकिन प्रशासनिक मसले और किसी खास तरीके पर फैसला करना एक मसला बना हुआ है। इस सिलसिले में प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत कंपनियों के खाते में धन देने की मौजूदा व्यवस्था के बदले किसानों के खाते में धन हस्तांतरित करने के तरीके की जांच की जा रही है।

बहरहाल पीएम किसान योजना के तहत किसानों को एक निश्चित धन दिए जाने में देरी की वजह से किसानों को चिंता है और खाद्य सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकदी अंतरण भी विवादास्पद मसला बना हुआ है। पीएम किसान की दूसरी किस्त का हस्तांतरण अक्टूबर तक होना था, जिसे इस महीने के पहले सप्ताह तक पूरा किए जाने की संभावना है।

क्रिसिल रिसर्च की निदेशक हेतल गांधी ने कहा, 'सरकार को समय बीतने के साथ इनपुट सब्सिडी के बजाय आउटपुट बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बुनियादी ढांचे में सुधार, लॉजिस्टिक्स, कृषि जिंसों के निर्यात की संभावनाओं की तलाश ढांचागत मसले हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अंतरिम व्यवस्था के तहत इनपुट सब्सिडी जारी रहनी चाहिए। इसके लिए सीधी सब्सिडी की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण है।'

उर्वरक मंत्रालय भी विभिन्न वैश्विक तरीकों का अध्ययन कर रहा है कि किस तरह से सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। केंद्रीय उर्वरक सचिव ने हाल ही में एक टीवी साक्षात्कार में कहा था कि नाइजीरिया में ई कूपन दिए जाते हैं और कई अन्य देशों में ई-वाउचर और पेपर वाउचर की व्यवस्था है। उनके मुताबिक अन्य तरीकों में उत्पादित फसल पर सब्सिडी की गणना जैसी व्यवस्था भी है। उन्होंने कहा था कि भारत को ऐसा तरीका अपनाना होगा, जो यहां के किसानों के अनुकूल हो।

यूरिया के मामले में सब्सिडी का सीधा भुगतान किसानों को करने की जगह आदर्श स्थिति यह होगी कि पोषक आधारित सब्सिडी दी जाए और यूरिया के दाम विनियंत्रित किया जाए। इसे लागू करने की अपनी जटिलताएं हैं व किसानों को सीधे भुगतान के अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। जहां तक कृषि का संबंध है, केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन के साथ अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेज बढ़ोतरी की, जिसकी वजह से खरीद प्रक्रिया में कमजोरियां आ रही हैं।

गेहूं और चावल के दाम समर्थन मूल्य से नीचे आने पर भारतीय खाद्य निगम प्रभावी तरीके से नियंत्रण करता है। लेकिन दलहन व तिलहन के मामले में व्यवस्था में कुछ खामियां पाई गईं, जब दाम लंबी अवधि तक समर्थन मूल्य से नीचे रहे और सरकार बुनियादी ढांचे के मसले या अन्य वजहों से खरीद में सक्षम नहीं थी।

बहरहाल एफसीआई पर बहुत ज्यादा कर्ज है और उसके पास स्टॉक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है और भंडारण की जगह भी नहीं है, जिससे गेहूं की नई फसल खरीदकर रखी जा सके, जिसकी खरीद अप्रैल से होनी है।

भारतीय कपास निगम के पास भी पिछले साल की खरीद का 10 लाख गांठ स्टॉक है और इस सीजन के अंत तक 50 लाख गांठ और खरीदने की योजना बना रहा है क्योंकि कीमत एमएसपी से नीचे चल रही है। इस तरह की सभी खरीद पर ढुलाई और गोदाम प्रबंधन, कार्यशील पूंजी आदि की भारी लागत आती है और उस जिंस की गुणवत्ता खराब होने की समस्या बनी रहती है।

नीति आयोग ने भावांतर योजना की तर्ज पर मोदी-1 सरकार के दौरान किसानों को मुआवजा देने को लेकर योजना तैयार की थी। दूसरी बार मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद यह योजना तत्काल सौंपी गई, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इसके विस्तृत अध्ययन की जरूरत है।

सरकार द्वारा सब्सिडी पर व्यय

प्रमुख मद	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
खाद्य सब्सिडी	1,00,282	1,71,298	1,84,220
यूरिया सब्सिडी	44,223	44,995	53,629
पोषक आधारित सब्सिडी	22,244	25,090	26,367

जिंस रु/क्विंटल	खरीद की लागत (एमएसपी) 2013-14	2018-19	2019-20
गेहूं	1,908	2,435	1,925
चावल	2,616	3,473	1,815-1835

आरई : संशोधित अनुमान, बीई: बजट अनुमान
स्रोतः बजट दस्तावेज व आर्थिक समीक्षा
बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित

पेंशन पर सरकार का खर्च कम

सेवानिवृत्ति की व्यवस्था और जनसांख्यिकीय संकेतक

देश	65 साल से ऊपर की आबादी* 2020	2060	सेवानिवृत्ति के साल पुरुष 2018	2060-65
भारत	11	29	21.1	23.4
जर्मनी	37	29	17.8	20.8
जापान	52	83	19.9	23.8
ब्रिटेन	32	52	18.7	20.1
अमेरिका	28	45	17.4	21.1

स्रोतः क्रेडिट सुइस *काम करने वाली उम्र की आबादी के % में

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 22 जनवरी

बुजुर्ग होती आबादी और दुनिया भर में जमा पर कम ब्याज दर से पूरी दुनिया में मौजूदा पेंशन प्रणाली पर दबाव पड़ रहा है। यह जानकारी एक अध्ययन में सामने आई है जिसमें कहा गया है कि वृद्ध पेंशन पर भारत का सार्वजनिक खर्च उसके जीडीपी का महज एक फीसदी है।

यह अध्ययन क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआरआई) ने कराया है जिसमें बूढ़ी होती आबादी के लिए तत्काल सेवानिवृत्ति के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। संस्था कहती है कि बचत की अवधि बढ़ाने और औसत पेंशन भुगतान अवधि को घटाने के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र में क्रमिक बढ़ोतरी उचित समाधान हो सकता है।

विकसित देशों में 65 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी की हिस्सेदारी 1950 के दशक में रहे 7.7 फीसदी से बढ़कर आज 19 फीसदी से अधिक हो चुकी है और 2050 तक अनुमानित तौर पर यह बढ़कर 27 फीसदी पर पहुंच सकती है। इसके उलट विकासशील देशों में यह अनुपात 1950 के दशक में 3.8 फीसदी था जो 2020 में 7.4 फीसदी होने का अनुमान है।

विकासशील देशों में वृद्ध पेंशन और आश्रितों के लाभों पर सार्वजनिक खर्च बहुत चिंताजनक है। उदाहरण के लिए भारत और इंडोनेशिया में यह खर्च जीडीपी का महज एक फीसदी है। जबकि जर्मनी, जापान और स्विटजरलैंड जैसे देशों में यह खर्च 10 फीसदी है। एक ओर जहां भारत में पुनर्स्थापन दर 95 फीसदी है वहीं कवरेज दर या सेवानिवृत्ति की उम्र से अधिक वाली आबादी की संख्या इंगित करती है कि पेंशन पाने वाले लोग भारत के मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में अधिक है।

विकासशील देशों के प्रतिक्रिया देने वाले 44 फीसदी लोगों ने कहा कि वृद्धावस्था में अपनी आय का बड़ा स्रोत वे व्यक्तिगत जमाओं और निवेश को समझते हैं। ऐसे लोगों की सबसे अधिक संख्या ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे देशों में है। विकसित देशों में यह आंकड़ा 40 फीसदी है।

लोग सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंचने के बाद भी काम करना जारी रखना चाहते हैं कि नहीं इसके निर्धारण में संबंधित देश की विकास की स्थिति एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकासशील देशों के करीब 53 फीसदी प्रतिक्रियादाताओं ने काम जारी रखने की इच्छा जताई जबकि विकसित देशों में ऐसे लोगों की संख्या महज 28 फीसदी थी।

इंडिया रेटिंग को आगामी बजट में राजकोषीय चूक की उम्मीद

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 22 जनवरी

आगामी आम बजट के 10 दिन पहले इंडिया रेटिंग ने कहा है कि भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत हो सकता है। बजट अनुमान में घाटा 3.3 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई थी।

वित्त वर्ष 2021 के बारे में अपने अनुमान में एजेंसी ने घाटा 3.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद जतई है, जबकि वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में 3 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।

एजेंसी ने कहा है कि अगर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए जरूरी हो तो सरकार को पूर्व नौकरशाह एनके सिंह की अध्यक्षता वाले एफआरबीएम पैनल की सिफारिशों के मुताबिक राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी करनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि अर्थव्यवस्था में मंदी या तेजी की स्थिति में सरकार घाटे के लक्ष्य में 0.5 प्रतिशत अंक का बदलाव कर सकती है। इसमें अनुमान लगाया है कि मौजूदा मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 में 9.3 प्रतिशत रहेगी जबकि अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में 7.5 प्रतिशत रहेगी। वित्त वर्ष 2020 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 12 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इंडिया रेटिंग में मुख्य अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा, 'वित्त वर्ष 2021 में भी कम जीडीपी वृद्धि दर जारी रहने का मतलब यह हुआ कि राजस्व वसूली कम होगी और व्यय बढ़ाने की सीमित संभावना होगी।'

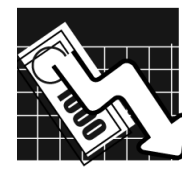

मंदी का पड़ेगा असर

इंडिया रेटिंग ने कहा है कि मंदी कुछ वजहों की वजह से आई है, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्ज वितरण में बहुत ज्यादा गिरावट, परिवारों की आमदनी वृद्धि कम होना, बचत में कमी और बहुत ज्यादा लिवरेज शामिल है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि 2020-21 में स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रहेगी, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) क्और विश्व बैंक के 5.8 प्रतिशत के अनुमान की तुलना में कम है। सिन्हा ने कहा कि 2020-21 में कुछ सुधार की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा जोखिम बने रहेंगे।

बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 22 जनवरी

भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करीब 25 प्रतिशत बढ़कर 28.74 अरब डॉलर हो गया है, जो 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है। सद्भाव इंजीनियरिंग की 9 सड़क परियोजनाओं में 2019 में प्रमुख रूप से निवेश आया। 2018 में इस क्षेत्र में 22.91 अरब डॉलर निवेश हुआ था।

बहरहाल एक्युरिस कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक सौदों की संख्या 64 से घटकर 58 पर आ गई है। 2019 में सद्भाव इंजीनियरिंग की 9 सड़क परियोजनाओं की 9935 लाख डॉलर में कनाडा पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) समर्थित बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) को बिक्री 2019 में भारत का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा एमऐंडए सौदा था। इस सौदे से भारत के सड़क क्षेत्र में निवेशक की रुचि का भी पता चलता है।

कुल निवेश में ऊर्जा क्षेत्र में 31 प्रतिशत, बिजली और परिवहन क्षेत्र में क्रमशः 25 और 24 प्रतिशत निवेश आया है। इसकी तुलना में 2018 की स्थिति देखें तो अक्षय ऊर्जा में सबसे ज्यादा 35 प्रतिशत निवेश आया था।

विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के मामले में देखें तो बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट को गति मिली है ।

बीएस सूडोकू 3646

7	1		3			8	2	
	3	4		8	2	5		7
	8				9	1		
		7	2	3			5	
8	9						7	3
	2			7	1	6		
		6	8				9	
2		9	4	1		3	8	
	4	8			6		1	2

परिणाम संख्या 3645

7	5	6	2	9	8	4	3	1
8	3	9	4	5	1	6	7	2
4	1	2	7	3	6	5	8	9
1	2	4	8	6	7	3	9	5
5	8	7	3	2	9	1	4	6
6	9	3	1	4	5	8	2	7
2	4	5	9	1	3	7	6	8
9	7	1	6	8	4	2	5	3
3	6	8	5	7	2	9	1	4

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान
★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2040/2050, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4300/4350, तिल सफेद 8900/9100, सोया (टीन) 1550/1600, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1475/1575,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3350, चावल (सोना) 2900/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1400, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1480, फ्लैक 1420, डीएमओ 1000, टरपीन लैस बोल्ड 1510

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1200/1220, खुरपा 1100/1125,चाकू 1060/1150, रसकट 940/950, शक्कर 1200/1220, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3310, सिहोरा 3300, बुंदकी 3260, बुढ़ाना 3320,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1100/1130, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4300, खलः सरसों 2200/2300, बिनौला 2400/2550, चना छिलका 2190/2200,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2100/2110, मक्की 2150/2175, बाजरा 1920/1925, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3825/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहनः सरसों (मिल पहुंच) 4490/4500,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3825, जौ 2130/2140,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7300/7400, बाजरा (गुजरात) 1900/1925, बाजरा (जयपुर) 1900/1925, चना 4100/4200, काबली चना 5000/6000, मूंग 7000/7100,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)126, राइसब्रान (अखाद्य) 123, खल सरसों 1960, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 7800/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7400/8400, उड़द धोया 9000/9900, छिलका 8700/9400, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5500,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3800, शरबती स्टीम 4100/4150,चावल 1509 सेला 5200/5225, धानः शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4080/4115, हरियाणा 4060/4080, राजस्थान 4000/4080, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2400/2500, सरसों खल 2080/2100,

फाजिल्का
गेहूं 2130/2140, सरसों 4300/4375 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4100/4110, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2000/2060, चावल परमल कच्चा 2400/2425, से ला 2350/2375, मक्की यूपी 2175/2200, दाल उड़द छिलका 9000/10200, चना देशी 4800/4900, दाल चना 5100/5200, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 8000/8500,

करनाल
गेहूं दड़ा 2020/2025, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2950/3000, पूसा 1509 धान 2850/2875, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5250, स्टीम 6050/6150,

हिसार
ग्वार 3825/3850, जौ 1840/1850, सरसों 4050/4100, मूंग 6900/7000, गेहूं 2080/2100,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1090, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 400/500, रिफाइंड (टीन) 1600/1620,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 4150/4200, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 9000/9050, गेहूं 2150/2175, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1850/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 290

खत्म हो संरक्षणवादी रुख

बीते कुछ वर्षों की बात करें तो भारत ने टैरिफ में कमी करने की अपनी नीति को उलटकर संरक्षणवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। हकीकत यह है कि आए दिन आयात प्रतिस्थापन के सरकारी प्राथमिकता में होने की बात होने लगी है। इसके पीछे यह अतार्किक दलील दी जाती है कि देश के घरेलू उद्योग शिशुवत हैं और उन्हें बचाव की आवश्यकता है। हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त मदिरा खरीद को सीमित करने तथा अन्य श्रेणी में कई अन्य उत्पादों के आयात को सीमित करने के प्रस्ताव में भी संरक्षणवाद की झलक महसूस की जा सकती है। हाल के वर्षों में प्रस्तुत बजट में भी आयात शुल्क बढ़ाकर खुलापन लगाने की चौथी सदी पुरानी प्रक्रिया को उलट दिया गया। वर्ष 2019-20 के बजट में वह प्रक्रिया जारी रखी गई जिसके तहत आयात शुल्क मनमाने ढंग से बदला गया। काजू से लेकर संगमरमर और फर्नीचर से लेकर वाहन कलपुर्जों तक तमाम वस्तुओं के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया। परंतु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए शुल्क बढ़ाने से उत्पादन की लागत बढ़ती है और वह गैर प्रतिस्पर्धी होता है। इसका असर लोगों के जीवन पर भी पड़ता है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला के दौर में शुल्क बढ़ाने और व्यापार समझौतों से बाहर रहने से केवल भारतीय निर्यातकों का नुकसान हो रहा है। इससे निवेश संभावनाएं धूमिल होती हैं और वृद्धि में धीमापन आता है। जाहिर है कि अपनी व्यापार नीति में मनमाना बदलाव करने वाला देश या घरेलू लॉबीइंग के कारण शुल्क बढ़ाने वाला देश ऐसी मूल्य श्रृंखला में शामिल नहीं हो पाएगा। संरक्षणवादी नीति और शुल्क दरों से जुड़ी अनिश्चितता विदेशी कंपनियों को भारत में अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को लेकर हतोत्साहित करेगी। ऐसे निर्णय भारतीय उद्योगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि किसी भी उद्योग के शुल्क में बढ़ोतरी अन्य उद्योगों में उसके उपयोगकर्ता को प्रभावित करेगी। व्यापारिक साझेदार इस पर प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं।

सबसे बुरी बात, सरकार के इस रुख में विदेशी निवेशकों को लेकर शत्रुता का भाव नजर आता है। प्रधानमंत्री भले ही अपने स्तर पर भारत के प्रचार-प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ते लेकिन उनकी सरकार के बाकी हिस्से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते नहीं दिखते। घाटे में चल रही विदेशी स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को हाल ही में लुटेरा करार दिया गया। ई-कॉमर्स में हुए निवेश को लेकर यह नकारात्मकता ऐसे निवेश से बनने वाले लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे और रोजगारों के प्रति जोखिम पैदा करती है। सरकार ने कई बार कहा है कि वह भारत को निवेश के अनुकूल बनाना चाहती है। उसने नियमन आसान बनाने, संचालन सुधारने और बुनियादी परियोजनाओं को विश्व भर में पेश करने जैसी कवायद की है। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि निवेश के बाद नियम बदलने से भारत की निवेशकों के अनुकूल छवि खराब होती है।

कुलमिलाकर यह स्पष्ट है कि यदि सरकार को मौजूदा मंदी के प्रभाव से निपटना है तो उसे अपना रुख बदलना होगा। इस मंदी के मूल में भी कमजोर निजी निवेश और मांग में गिरावट जैसी वजह ही हैं। समस्या का इकलौता हल खुलापन बढ़ाने में है। ऐसा करके ही वैश्विक बाजार की संभावनाओं का पूर्ण लाभ लिया जा सकता है। फिर चाहे बात पूंजी जुटाने की हो या उत्पादों की। सरकार का संरक्षणवादी रुख देश को पीछे धकेलने का काम करेगा। ऐसी लॉबी की बात सुनने के बजाय नीति निर्माताओं को ऐसी परिस्थितियां तैयार करनी चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। आम बजट के रूप में सरकार के पास यह अवसर है कि वह संरक्षणवाद से किनारा कर सके।

अजय मोहंती

क्या अनचाहे हो रहा है अतिशय नियमन ?

अफसरशाही द्वारा नियम कायदों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना और इस तरह कारोबारियों को परेशान करना अनजाने में हो रहा है या यह सोच समझकर किया जा रहा है ? बता रहे हैं **देवाशिष बसु**

बीते सात वर्षों से एक अटके हुए रिकॉर्ड की तरह मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं कि भारत उच्च वृद्धि हासिल कर सकता है लेकिन लालफीताशाही का अंतहीन सिलसिला उद्यमों के लिए टकराव की वजह बन रहा है। जबकि ये उद्यम ही असली रोजगार प्रदाता हैं। इन दिनों तो रोजगार प्रदाताओं को राजनेताओं के ताने और उनके हाथों अपमान भी झेलना पड़ता है। कारोबारी आमतौर पर इसे स्वीकार कर लेते हैं। बहरहाल, ऐसा लगता है कि बीते छह वर्ष में आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक जो नाकामियां हाथ लगी हैं और इस दौरान जो दंडात्मक शासन देखने को मिला है, वह लोगों को एक नई हकीकत से रूबरू करा रहा है।

भारत की वृद्धि दर लंबे समय तक कमजोर बनी रहेगी। हालांकि अर्थव्यवस्था वापसी करेगी लेकिन अतीत से बचकर निकलना मुश्किल है। कारोबारियों का धैर्य अब समाप्त होने को है और वे बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीते सप्ताह हमने देखा कि देश के दो शीर्ष उद्योगपति अत्यधिक नियमन, एक हद तक जबरन वसूली, नीतियों में मनमानी छेड़खानी और यहां तक कि प्रक्रिया के दौरान प्रताड़ना तक की शिकायत कर रहे हैं।

राजीव बजाज, जो अब तक कह रहे थे कि कोई मंदी नहीं है और अन्य उद्यमियों की पर्याप्त नवाचारी न होने के लिए आलोचना भी कर रहे थे, वह अचानक एक अलग गाना गुनगुनाने लगे हैं। उनका आरोप है कि अतिशय नियमन से उद्योग जगत को नुकसान पहुंच रहा है। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कहते हैं, 'भारत सूक्ष्म प्रबंधन और आशंकाओं से ग्रस्त है। यदि उसे तेज गति से विकास करना है तो हमें उन बाधाओं को दूर करना होगा जो कारोबारों को घेरे हुए हैं।'

वर्ष 2014 से अधिकांश भारतीय कारोबारी यह मानते रहे हैं कि एक प्रतिबद्ध, राष्ट्रवादी सरकार नया भारत बनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा की गई थी कि वह गुजरात की अपनी बहुप्रचारित सफलता पूरे देश में दोहराएंगे। उन्होंने सन 2014 का चुनाव विकास के वादे पर जीता था। जहां तक मुझे याद है मोदी के रूप में पहली बार एक राष्ट्रीय नेता ने अपने चुनावी भाषणों में लालफीताशाही समाप्त करने की बात कही थी। उन्होंने उत्साहित युवाओं से पूछा था, 'आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए?' जाहिर है लोगों को उनसे उम्मीद थी कि वह कारोबारी जगत को बेतुकी लालफीताशाही से निजात दिलाएंगे। आखिर रोजगार कौन तैयार करता है? घर के आसपास मौजूदा किराना दुकान से लेकर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों तक यह काम कारोबार ही करते हैं, न कि सरकार।

दुर्भाग्य की बात है कि सन 2014 में ही सरकार का वास्तविक एजेंडा एकदम स्पष्ट हो गया था। यह बात दीगर है कि इसके बावजूद कारोबारी, वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ और मीडिया का अधिकांश हिस्सा व्यापक तौर पर भ्रम में ही जीता रहा। मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर ही कंप्यूटर चिप लगाने का काम जारी रखा क्योंकि अब सबकुछ डिजिटल हो चुका था। यही नहीं इन्हें नए नाम से नए विचारों के रूप में प्रचारित किया गया।

हर विधायी बदलाव और नीति ने केवल उत्पीड़न, अतिक्रमण, आशंका, अपराधीकरण आदि को बढ़ाने का काम किया। छोटी-छोटी गलतियों और चूकों के लिए जेल का दंड दिया गया। एक भ्रष्ट देश में ये निजी और सरकारी दोनों तरह के उत्पीड़न का जरिया बन गए। इस बीच सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे (गो संरक्षण, लिचिंग, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, कश्मीर, गांधी-नेहरू परिवार की कमियां आदि) ने आर्थिक बहस को पीछे छोड़ दिया।

एक कारोबारी क्षेत्र जो बुरी तरह प्रभावित हुआ वह है 150 सीसी की मोटर साइकिल की श्रेणी। यह एक बड़ा बाजार है। इसे पहला झटका तब लगा जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुरुआत में ही पांच साल का बीमा कराना अनिवार्य है। इससे वाहन कीमत में बीमा की कई हजार रुपये की राशि जुड़ गई। गत वर्ष अप्रैल में नए सुरक्षा मानकों से 8,000-10,000 रुपये और जुड़ गए। जैसा कि बजाज ने कहा कि केवल एक वर्ष में इन वाहनों की कीमत 20 फीसदी तक बढ़ गई। जबकि वाहन निर्माता कीमतों में सालाना 2 से 4 फीसदी का ही इजाफा करते हैं। बजाज ने कहा था, 'मैं इसे अतिशय नियमन मानता हूं। एक देश में जहां सड़कों की खस्ता हालत देखते हुए आप प्रतिघंटा 20 से 30 किलोमीटर से अधिक की गति से वाहन चलाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहां एबीएस जैसे सुरक्षा मानक के लिए 8,000 से 10,000 रुपये की लागत थोपना गलत है।'

उन्होंने कहा, 'यह कहना राजनीतिक दृष्टि से गलत हो सकता है कि बीएस-6 को अपनाना सही नहीं है बल्कि उपयुक्त तरीका अपनाकर पुराने वाहनों से निजात पाना, बीएस-4 से हो रहे उत्सर्जन को और कम करने का कहीं अधिक अच्छा तरीका है। इसके बजाय हम अप्रैल से बीएस-6 अपना रहे हैं यानी आम आदमी के लिए वाहन कीमतों में 8,000 से 10,000 रुपये का और इजाफा। यानी डेढ़ साल में आम आदमी के लिए दोपहिया वाहन 30 फीसदी तक महंगे। मेरे लिए यह बहुत कठिन मुद्दा है। क्या सरकार कुछ नरमी दिखाते हुए इनमें से कुछ कदम वापस लेगी?'

बजाज को जानना चाहिए कि राज्य सत्ता चाहे किसी दल की हो, नरमी उसका गुण नहीं है। इस सरकार ने तो आधार से होने वाली मौतों तक के लिए कोई खेद नहीं प्रकट किया और न ही नोटबंदी के भयावह असर को लेकर। बल्कि इसने कई राजस्व कानूनों में गिरफ्तारी और कैद के प्रावधान शामिल कर दिए हैं।

राजनीति

यह देखना सुखद है कि कारोबारी उन मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। परंतु एक सवाल का उत्तर बाकी है: सरकार अतार्किक रूप से दंडात्मक क्यों है? राजनेता कारोबारियों पर हमले क्यों कर रहे हैं और कानून हर किसी को अपराधी ठहराने पर क्यों तुले हैं? मुझे डर है कि बोलने वाले कारोबारी नेताओं और बाबुओं से लालफीताशाही कम करने की अपील करके दोबारा गलती कर रहे हैं।

जरा खुद से पूछिए कि आखिर क्यों मंत्री और उनके आईएएस सचिव निर्णय प्रक्रिया में देरी की लागत को क्यों नहीं समझते? उन्हें इतने नियमों, विविध लाइसेंस, अतीत से लागू होने वाले संशोधनों, लंबित अदालती मामलों, अतार्किक कर मांगों और दंडात्मक कानूनों से होने वाली दिक्कत क्यों नहीं दिखती? वे खुद को बढ़त दिलाने और कारोबारियों को उनकी जगह दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। वे चीजों को आसान बनाना नहीं चाहते। इन चीजों को सामान्य बनाने की मांग करने वाले राजनेता सीधे हैं। उन्हें इसके पीछे की राजनीति की समझ नहीं है।

मुद्रा एवं वित्त पर समग्र रिपोर्ट फिर से जारी करे रिजर्व बैंक

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

कई दशकों तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मुद्रा एवं वित्त पर समग्र रिपोर्ट प्रकाशित किया करता था। यह एक बेहतरीन रिपोर्ट होती थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बयां करने के साथ ही अभिलेख सामग्री के तौर पर भी काम करती थी।

अपने शुरुआती अवतार में इस रिपोर्ट में आर्थिक समीक्षा की तरह दो हिस्से- विश्लेषण और आंकड़े हुआ करते थे। फिर 2001 के आसपास आरबीआई की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका सामने आई। लिहाजा आरसीएफ के दूसरे संस्करण को बंद कर दिया गया। उसके बाद यह एक विषयवस्तु आधारित प्रकाशन रह गया जो हर दो साल में एक बार आता था। लेकिन 2013 के बाद इसका प्रकाशन अचानक बंद हो गया। आखिरी संस्करण वर्ष 2013 में आया था। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन और डिप्टी गवर्नर ऊर्जित पटेल ने रिपोर्ट छपनी बंद होने की कोई भी वजह नहीं बताई थी।

असल में, 2008-2013 के दौरान आरबीआई गवर्नर रहे डी सुब्बाराव को भी इसकी सफाई देनी पड़ी थी कि 2008 के बाद पांच वर्षों में एक ही रिपोर्ट क्यों आई? सुब्बाराव के कार्यकाल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था को लीमन संकट का सामना करना पड़ा था। अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में सुब्बाराव गैर-जिम्मेदार राजकोषीय नीति को लेकर शिकायतें कर रहे थे। आखिरकार 2013 में प्रकाशित अंतिम आरसीएफ रिपोर्ट में ये तमाम चिंताएं राजकोषीय एवं मौद्रिक विमर्श पर सुविचारित लेखों के रूप में नजर आईं। उसके बाद रघुराम राजन और ऊर्जित पटेल को यह बताने की जरूरत पड़ी कि उन्होंने आरसीएफ को चुपचाप क्यों दरकिनार कर दिया? आखिरकार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के पूर्ण खुलासे और त्वरित सुधारात्मक कदमों की शुरुआत होने के बाद इसकी सख्त जरूरत थी कि अगले आरसीएफ में वित्तीय स्थिति का सही लेखा-जोखा पेश किया जाए।

राजन को वह वजह भी बतानी चाहिए थी कि उन्होंने बैंकिंग प्रणाली में बेसल-3 मानक लागू करने का फैसला क्यों किया? निश्चित तौर पर उनके पास ठोस कारण रहे होंगे लेकिन वे क्या थे? क्या इस पर सही ढंग से चर्चा हुई थी? आरसीएफ यह बताने की सबसे अच्छी जगह होती। हम सभी यह समझ जाते और आरबीआई इतिहास के लेखकों को भी फाइलों तक पहुंच न होने से काफी मशक्कत करनी होती।

मेरी शिकायत यह है कि अगर राजन और पटेल ने यह सोचा था कि आरसीएफ जरूरतों को लेकर निरर्थक था तो उन्हें यह बताना चाहिए था कि उन्हें ऐसा क्यों लगा? अगर उन्होंने रिपोर्ट को खराब ढंग से लिखा हुआ माना तो वे सुधार सकते थे। इसके बजाय उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति की तरह मनमाने ढंग से काम किया। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण न होने से यह देखने में तो ऐसा ही लगता है।

यह सवाल भी उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ऐसा हुआ रहता तो क्या प्रतिक्रिया रही होती? लेकिन 2013 में किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार मरणासन्न थी और सरकार में बैठे किसी भी शख्स ने इस पर गौर नहीं किया।

आरबीआई शोध की बहाली

आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र के पास शोध विभाग का जिम्मा होने से यह उम्मीद बंधती है कि आरबीआई इस समग्र रिपोर्ट को फिर से जारी करना शुरू करेगा। आखिर डॉ पात्र ने आरबीआई के साथ अपने लंबे करियर में इस रिपोर्ट पर कभी-न-कभी जरूर काम किया होगा लिहाजा वह किसी बाहरी व्यक्ति की तुलना में रिपोर्ट की अहमियत समझने की बेहतर हालत में हैं।

इसके अलावा सात साल के लंबे अंतराल के बाद देश की मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिति के बारे में समग्र रिपोर्ट आने से नए मौद्रिक सिद्धांतों एवं वैश्विक प्रवृत्तियों को समझने का शानदार अवसर भी मिलेगा। इनके आधार पर भारतीय परंपराएं भी शुरू की जा सकती हैं। डॉ पात्र के जिम्मे केवल यही काम नहीं होगा। आरबीआई को 'ओकेजनल पेपर्स' रिपोर्ट भी जारी करनी है। इसमें आरबीआई के अपने अधिकारियों के शोधपरक लेख शामिल होते हैं। इसका पिछला संस्करण गत जुलाई में आया था। हरेक छह महीने पर जारी होने वाली रिपोर्ट के नए संस्करण का वक्त आ गया है। इसके साथ एक समस्या यह है कि यह एक व्यर्थ रिपोर्ट हो चुकी है और इसकी गुणवत्ता में भी अस्थिरता देखी जाती रही है। जो भी हो, इससे यह जानकारी तो मिल ही जाती है कि आरबाई किस तरह के शोध को बढ़ावा दे रहा है? डॉ पात्र को इस रिपोर्ट का प्रकाशन भी अपने हाथ में लेने की जरूरत है ताकि उसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के मुताबिक ढाला जा सके। ओकेजनल पेपर्स का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि आरबीआई के बाहर के विशेषज्ञ भी उसमें अपने लेख प्रकाशित होने की मंशा रखने लगें। उबाल इतना अधिक है कि हम सांस्थानिक आधार पर उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसका बड़ा हिस्सा ट्विटर उपयोगकर्ताओं के रहमोकरम पर छोड़ा जा चुका है। खासकर मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रयास में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अर्थशास्त्रियों को अपने साथ जोड़ें। उनके पास भले ही विदेशी विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की डिग्री न हो लेकिन वे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को कहीं बेहतर ढंग से समझते हैं।

पिछले वर्षों में आईईएस एक तरह से अधीनस्थ सेवा बनकर रह गई है जिसे किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसकी वजह यह है कि आईईएस अधिकारियों के प्रमुख यानी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पास इसके लिए वक्त ही नहीं होता है। कौशिक बसु इसके इकलौते अपवाद थे।

मुझे पूरा भरोसा है कि डॉ पात्र को वित्त मंत्री का भरपूर सहयोग मिलेगा। वित्त मंत्री को कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की जरूरत है, न कि हमेशा अपना रिज्यूमे सुधारने की कोशिश में लगे रहने वाले लोगों की।

कानाफूसी

घर में ही आलोचना

संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ताओं में दुनिया को यह दिखाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं कि स्थायी विकास और आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र में नियमित और स्थायित्व भरी नीतियों की मदद से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। परंतु कुछ सदस्यों को अपने घर में ही कटु आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी 26वीं शिखर वार्ता की अध्यक्ष ब्रिटेन की क्लेयर ओनील भी ऐसे लोगों में शामिल हैं। दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक गोलमेज बैठक में उन्होंने एक मां से कहा, 'मेरी बेटी पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रही एक प्रदर्शनकारी है। वह मुझसे कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं वह पर्याप्त नहीं हैं। मैं जवाब में उससे यही कहती हूं कि मैं जो कुछ कर सकती हूं कर रही हूं।' गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित आयोजित एक बैठक में एक छात्रा ग्रेटा थनबर्ग के बयान ने दुनिया को इस पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया।

मध्य प्रदेश के दामाद

जगत प्रकाश नड्डा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में खासी खुशियां मनाई गईं। खासतौर पर प्रदेश के जबलपुर शहर में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कारण? नड्डा की पत्नी मल्लिका जो हिमाचल प्रदेश में इतिहास की प्रोफेसर हैं, वह जबलपुर से ताल्लुक रखती हैं। यही कारण है कि नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद उनके परिवार के पड़ोसी मिठाइयां बांटते देखे गए। नड्डा की सास जयश्री बनर्जी मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा, दोनों स्थानों पर जबलपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने नड्डा को मध्य प्रदेश का दामाद कहते हुए बधाई दी। नाथ ने कहा, 'राज्य के दामाद नड्डा जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई।'

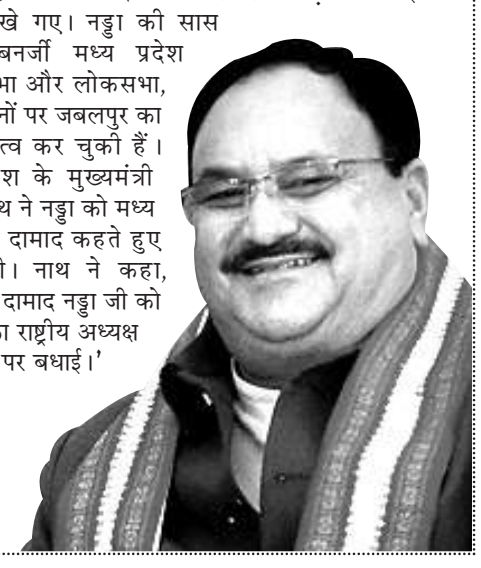

आपका पक्ष

देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां

ऐसा कहा जाता है कि जिस देश की आंतरिक सुरक्षा जितनी मजबूत होगी, वह देश उतना ही दीर्घजीवी होगा। अन्यथा वह अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। यह आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा चर्चा के केंद्र में इसलिए आया कि हाल में जम्मू कश्मीर में पदस्थापित एक डीएसपी दविंदर सिंह दो आतंकियों को अपनी कार से श्रीनगर ले जा रहा था। उन आतंकियों का संबंध हिजबुल मुजाहिद्दीन से था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। सवाल यह उठता है कि क्या वजह है जो कुछ लोग आसानी से देश की सुरक्षा का सौदा करने को तैयार हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर दविंदर सिंह का उदाहरण देखें तो 12 लाख रुपये के लिए उसने यह सौदा किया। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल में कमी, आतंकी फंडिंग, धनशोधन, हवाला, साइबर हमले आदि ऐसे कारक हैं जो समय-समय पर आंतरिक सुरक्षा की अग्नि परीक्षा लेते रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा में चूक के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जो देश की एकता एवं अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक एजेंसियों का गठन किया गया और कानून पारित किए गए हैं। वर्ष 2008 के मुंबई हमले के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन किया गया। इसके अलावा आईबी, डीआरआई, सीईआरटी-इन आदि आंतरिक सुरक्षा के लिए समर्पित जांच एजेंसियों को स्थापित किया गया। आतंकवाद रोकने के लिए संसद से टाडा, पोटा जैसे कानून पारित किए गए। वर्तमान में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन ऐक्ट 1967 (यूएपीए) इस दिशा में प्रभावी है, जिसमें हाल ही में 2019 में पांचवां संशोधन किया गया। इसके तहत भारत में पहली बार ऐसी कानूनी व्यवस्था की गई कि किसी व्यक्ति के भी आतंकी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। इससे पूर्व यह व्यवस्था सिर्फ संगठन पर ही लागू था। बहरहाल, सर्वप्रथम सुरक्षा एजेंसियों, राज्य की पुलिस और अन्य सभी साझेदारों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। अत: देश की अखंडता व एकता के लिए आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर और प्रभावी तरीके से बढ़ना होगा।

द्विजेंद्र कौशिक, ईमेल से

मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिछले दिनों सारंग तोप का सफल परीक्षण किया गया *-पीटीआई*

साफ पानी कैसे मिल पाएगा

हाल में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं होगा। देश के कई राज्यों में जल संकट ने दस्तक दे दी है। इन राज्यों का भूजल स्तर गिरता जा रहा है। मोदी सरकार ने देश के हर घर तक नल से जल की योजना का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर बारिश के कम होने के कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब लोग साफ पानी के लिए तरस जाएंगे। यह कहना उचित होगा कि जब देश में सूखे की स्थिति पैदा होती है तब पानी बचाने के उपाय करने लगते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। अत: बारिश के पानी को संभालना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए साफ पानी बचाकर रखना है तो सभी लोगों को हर हाल में पानी बचाने का प्रण करना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

राज्यों के ग्रिडों ने चीनी मिलों द्वारा उत्पादित बिजली की कीमतों में की भारी कटौती

बिजली दर घटीं, चीनी मिलों पर दबाव

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 22 जनवरी

चीनी क्षेत्र में समस्याएं दूर करने के लिए केंद्र के कई सकारात्मक कदमों के बावजूद मिलों के मुनाफे पर चालू पेराई सत्र के दौरान दबाव बरकरार रहने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि राज्यों के ग्रिडों ने चीनी मिलों द्वारा उत्पादित बिजली की कीमतों में भारी कटौती की है।

चीनी मिलों द्वारा शीरे अपशिष्ट का इस्तेमाल कर बिजली तैयार की जाती है। जहां चीनी मिलों द्वारा उत्पादित कुछ बिजली का इस्तेमाल निजी खपत में किया जाता है, वहीं अधिशेष बिजली की आपूर्ति निर्धारित कीमत पर राज्य ग्रिडों को की जाती है जिसके लिए पिछले साल महाराष्ट्र और कर्नाटक में 5-6 रुपये प्रति यूनिट की कीमत प्राप्त हुई थी। हालांकि बिजली की औसत कीमत पिछले वर्षों में 6.50 रुपये प्रति यूनिट रही है, जो अब घटकर 3-3.50 रुपये प्रति यूनिट रह गई है।

औसत विद्युत कीमत इस साल 50 प्रतिशत तक घटी है। शीरे के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर चीनी मिलें अपने परिसरों में बिजली का उत्पादन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'बिजली का हमारे कुल कारोबार में लगभग 5-7 प्रतिशत का योगदान है। लेकिन इसमें से ज्यादातर कारोबार प्रत्यक्ष रूप से मुनाफे में तब्दील होता है, क्योंकि इस तरह के बिजली उत्पादन में काफी कम खर्च आता है। इसलिए, बिजली की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट का निश्चित तौर पर हमारे मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चीनी उद्योग विद्युत खरीद कीमतों में वृद्धि के लिए संबद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहा है।'

बिजली राज्य का मामला होने की वजह से केंद्र का विद्युत कीमतों के निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। सामान्य तौर पर, चीनी मिलें अपनी व्यावसायिक बिजली बेचने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार के साथ विद्युत खरीद समझौता करती हैं।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अबिनाश वर्मा ने कहा, 'हमें विद्युत उत्पादन के संदर्भ में सरकार से निराशा का सामना करना पड़ा है। सौर और पवन ऊर्जा स्रोतों से सस्ती बिजली की उपलब्धता की वजह से लगभग सभी राज्य सरकारों ने बिजली कीमतें 40-50 प्रतिशत तक घटाने का निर्णय लिया है। यह चीनी मिलों के लिए काफी हद तक नकारात्मक है।'

विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की कीमतें घटाकर अब 3 रुपये प्रति यूनिट कर दी हैं, जबकि पिछले साल ये 5 रुपये प्रति यूनिट थीं।

चीनी मिलों को अधिक एथनॉल उत्पादन की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र ने सितंबर 2019 में एथनॉल कीमतें 1.84 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाई थीं। सरकार ने दिसंबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच कच्चे तेल आयात का बिल 1 अरब डॉलर तक घटाने के प्रयास के तहत एथनॉल कीमतों में यह वृद्धि की थी। एथनॉल को वाहन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है।

सी-हैवी श्रेणी के शीरे से उत्पादित एथेनॉल की कीमत 29 पैसे तक बढ़कर 43.75 रुपये प्रति लीटर जबकि बी-हैवी शीरे के लिए 1.84 रुपये तक बढ़कर 54.27 रुपये प्रति लीटर की गई है।

जहां सरकार ने चीनी की न्यूनतम कीमत 31 रुपये प्रति किलोग्राम (महाराष्ट्र में एस वेरायटी की चीनी) निर्धारित की है, वहीं इसकी कीमत 50-75 पैसे तक की वृद्धि के साथ मौजूदा समय में 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एम श्रेणी की चीनी का भाव बढ़कर 33.5-34 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।

चीनी मिलों का घटा मुनाफा

- मिलों का मुनाफा प्रभावित हुआ है, क्योंकि मिलों की आय में बिजली की बड़ी भागीदारी है
- शीरे के अपशिष्ट से चीनी मिलें अपने परिसरों में बिजली का उत्पादन कर रही हैं
- सौर और पवन ऊर्जा की बिजली सस्ती होने पर कीमत 40-50 फीसदी तक घटीं
- उत्तर प्रदेश ने बिजली की कीमतें 3 रुपये प्रति यूनिट की जो पिछले साल 5 रुपये थी

तांबा उत्पादक चाहते कम आयात शुल्क

गुणवत्तापूर्ण कॉपर कॉन्सन्ट्रेट का भंडार नहीं होने से करना पड़ता है आयात

जयजित दास
भुवनेश्वर, 22 जनवरी

आम बजट 2020-21 आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। भारतीय तांबा उत्पादकों ने कॉन्सन्ट्रेट आयात पर 2.5 प्रतिशत छूट की मांग की है। इस शुल्क छूट से उन तांबा विनिर्माताओं को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके लिए तैयार उत्पादों के आयात से मुकाबला करना मुश्किल रहता है। इन उत्पादों की आपूर्ति आमतौर पर उन देशों से होती है जिन्हें भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ मिलता है।

उद्योग के एक सूत्र ने कहा कि भारतीय स्मेल्टर 'कस्टम स्मेल्टर' हैं और अपनी करीब 95 प्रतिशत जरूरत के लिए आयातित कॉपर कॉन्सन्ट्रेट पर निर्भर रहते हैं। घरेलू स्मेल्टर के प्रतिकूल कारोबारी प्रारूप को देखते हुए वे नुकसान की स्थिति में हैं, जबकि अपनी खदान रखने का लाभ उठाने वाले देशों के स्मेल्टरों की एकीकृत प्रकृति से उन्हें लाभ मिलता है। मौजूदा उलट शुल्क संरचना की वजह से यह स्थिति और बदतर हो जाती है जिससे घरेलू स्मेल्टरों को कच्चे माल यानी कॉपर कॉन्सन्ट्रेट पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क वहन करना पड़ता है। जबकि देश में तैयार उत्पाद शून्य शुल्क पर (आसियान-एफटीए से) आयात किए जाते हैं।

देश में कॉपर कॉन्सन्ट्रेट का गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त भंडार नहीं होने के कारण घरेलू विनिर्माताओं के लिए इसका आयात जरूरी हो जाता है। चीन, जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे प्रमुख तांबा उत्पादक देश पहले ही शून्य शुल्क पर कॉपर कॉन्सन्ट्रेट का आयात कर रहे हैं। इससे भारतीय स्मेल्टरों को एक समान कार्य क्षेत्र नहीं मिल पाता है क्योंकि उन देशों में कॉपर कॉन्सन्ट्रेट पर शून्य आयात शुल्क के कारण स्मेल्टरों की लागत कम रहती है।

चीन और जापान जैसे देशों में कॉपर कॉन्सन्ट्रेट को संरक्षण मिल रहा है। इन देशों ने क्रमशः अफ्रीका और चिली में तांबा खदानों के साथ निवेश-रणनीतिक समझौते किए हुए हैं। इससे भारतीय स्मेल्टरों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर जोखिम पैदा हो रहा है।

सूत्र ने कहा कि तांबे जैसे अधिक मूल्य वाले उत्पाद के लिए 2.5 प्रतिशत आयात शुल्क बड़ी राशि होती है। घरेलू उद्योग पहले ही लगातार बढ़ते आयात और कम होती घरेलू हिस्सेदारी की पृष्ठभूमि में कम मार्जिन पर परिचालन कर रहा है। एफटीए के प्रभाव के साथ-साथ इस उलट शुल्क संरचना से घरेलू तांबा स्मेल्टरों की प्रतिस्पर्धी क्षमता समाप्त हो रही है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 19 के दौरान तांबे में 4.3 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 11 में 1.2 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष था।

स्मेलटर क्षमता के अनुपात के रूप में कॉन्सन्ट्रेट उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है जो वर्ष 2016 में 83.2 प्रतिशत था और वर्ष 2019 में गिरकर 78.4 प्रतिशत रह गया है। तांबा उत्पादकों को लगता है कि कॉन्सन्ट्रेट आयात पर शुल्क खत्म करना और उलट शुल्क संरचना को दुरुस्त करना उद्योग के अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा इस शुल्क छूट से 1,000 से ज्यादा एसएमई (सूक्ष्म एवं मझोले उद्यमों) को फायदा होने की उम्मीद है जिन्हें प्राथमिक तांबा उत्पादकों से मदद मिलती है। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को और परोक्ष रूप से चार लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।

- घरेलू तांबा उत्पादकों ने 2.5 प्रतिशत छूट की मांग की
- चीन, जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख तांबा उत्पादक देश शून्य शुल्क पर कर रहे हैं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट का आयात
- इस शुल्क छूट से 1,000 से ज्यादा सूक्ष्म एवं मझोले उद्यमों को फायदा होने की उम्मीद
- इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से एक लाख और परोक्ष रूप से चार लाख लोगों को मिल रहा है रोजगार

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 22	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,810.5	6.0	2,064.6	7.7
Copper	6,158.5	6.3	6,544.9	7.7
Nickel	13,750.0	-14.2	14,606.7	-15.1
Lead	1,952.0	-12.7	2,191.0	3.6
Tin	17,675.0	5.6	18,398.9	2.4
Zinc	2,455.0	-1.9	2,640.4	-0.9
Gold ($/ounce)	1,555.8*	4.6	1,743.7	4.2
Silver ($/ounce)	17.8*	1.4	20.1	0.8
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	63.7*	7.9	64.3	8.0
Natural Gas ($/mmBtu)	1.9*	-15.9	1.9	-15.8
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	202.9	16.4	291.2	-4.0
Maize	191.4*	4.4	276.1	-1.6
Sugar	405.9*	20.9	489.3	-0.2
Palm oil	765.0	41.7	1,220.2	39.6
Rubber	1,539.4*	12.2	1,924.2	11.4
Coffee Robusta	1,306.0*	7.3	1,776.7	-7.0
Cotton	1,533.1	7.5	1,616.8	0.2

* As on Jan 22, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.2& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	164.7	34769
Oil and Oilseeds	380.7	90098
Spices	1.1	10
Metal(Jan 21)		
Metal- non ferrous	5643.6	49295
Metal- precious	14168.5	428
Oil and gas(Jan 21)		
Gas	2718.5	64536
Oil	12225.1	1485

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	189.9	123410
Grains	115.0	99155
Oil and Oilseeds	965.7	479570
Others	90.9	65870
Pulses	111.6	29705
Spices	34.2	22649

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Feb 14)	3926.4	2.2
Zinc Mini (Jan 31)	184.3	0.9
Aluminium Mini (Jan 31)	142.1	0.5
Lead Mini (Jan 31)	151.8	0.5
Aluminium (May 29)	142.9	0.1
Crude Oil (Feb 19)	4186.0	0.1
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Jan 28)	134.5	-2.4
Nickel (Jan 31)	1015.5	-1.9
Zinc (May 29)	186.4	-1.8
Silver (Mar 05)	46143.0	-1.2
Silver Micro (Feb 28)	46168.0	-1.2
Silver Mini (Feb 28)	46167.0	-1.2

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	2022.0	0.4
Guar Seed 10 (Feb 20)	4122.0	0.4
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	7333.0	0.4
Losers (* % Change)		
Wheat-Kota (Feb 20)	2073.0	-2.9
Soyabean Indore (Feb 20)	4142.0	-1.8
Chana-Bikaner (Mar 20)	4089.0	-1.8
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	872.6	-1.7
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4211.0	-1.5
Jeera Unjha (Mar 20)	14595.0	-1.3
Coriander-Kota (Apr 20)	6849.0	-1.2
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	4102.0	-1.0
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6238.0	-0.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	2.2
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19570.0	1.7
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3926.4	0.7
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46168.0	0.2
Silver Ahm (Mar 05)	46143.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1229.5	-11.0
Alumini-Mumbai (Jan 31)	142.1	-3.5
Aluminium Mum (May 29)	142.9	-3.0
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	184.3	-2.7
Nickel Mumbai (Jan 31)	1015.5	-2.2
Lead Min Mumbai (Jan 31)	151.8	-2.0
Zinc Mumbai (May 29)	186.4	-1.6

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6238.0	2.6
Maize-Sangli (Feb 20)	1966.0	1.6
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1963.0	1.2
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	19490.0	1.0
Bajra-Delhi (Feb 20)	1963.0	0.7
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3215.0	0.5
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1730.0	-20.6
Jeera Unjha (Mar 20)	14595.0	-6.4
Soy Bean Indore (Feb 20)	4142.0	-3.9
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	780.2	-0.3
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	7333.0	-0.3

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals		Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	109	(109)
Aluminium ingots /kg	147	(147)
Brass sheet cutting /kg	333	(333)
Brass utensil scraps/kg	313	(313)
Copper heavy scrap /kg	434	(434)
Copper utensil scraps/kg	405	(405)
Copper wire bar /kg	466	(466)
Lead ingots /kg	156	(157)
Nickel Cathodes /kg	1040	(1045)
Tin slabs /kg	1310	(1315)
Zinc slabs /kg	188	(187)
Source:Bombay Metal Exchange		
Cotton		**Mumbai**
Bengal Deshi /Qtl	10292	(10292)
DCH - 32 /Qtl	11389	(11529)
Jaydhar /Qtl	9842	(9926)
Shankar- 6 /Qtl	11164	(11304)
Source:Cotton Association of India		
Oil		**Mumbai**
Castor FSG /10kg	882	(883)
Castor Comm /10kg	872	(873)
Ricebran oil/10kg	820	(820)
Groundnut oil /10kg	1140	(1140)
Linseed oil /10kg	965	(965)
Karanji /10kg	800	(800)
Palm oil /10kg	860	(855)
Sunflower exp ref /10kg	900	(900)
Sunflower oil exp /10kg	875	(880)
Soyabean ref / 10kg	895	(895)
Source:Bombay Commodity Exchange		

सॉफ्ट

Sugar		Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3585	(3382-3585)
Source:Bombay Sugar Merchants Association		

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel		
NYSE Crude	57.96	(58.38)
Brent Crude (UK)	63.66	(63.92)
Brent Crude (WTI)	58.34	(58.34)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.91	(1.9)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	334.86	(324.23)
Naptha spot /Rs/MT	45170	(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150	(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950	(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com		

सर्राफा

Gold		Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39916	(39854)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40076	(40014)
Silver.999/ kg	46110	(46410)
Source:India Bullion & Jewellers Association		

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19399.90	19289.95
Alumini-Mumbai (M)	1 K	145.05	147.25
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1970.00	1950.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1957.00	1939.55
Barley Jaipur (N)	1 Q	2186.25	2178.85
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3833.00	3900.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4204.30	4200.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4160.00	4175.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4228.00	4185.30
Chana Delhi (N)	1 Q	4400.00	4402.10
Chana-Akola (N)	X	4300.00	4200.00
Coriander-Gondal (N)	X	6600.00	6500.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6772.50	6600.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6847.30	6817.20
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2086.50	2058.50
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2054.45	2025.20
Cotton-Kadi (N)	1 B	19337.75	19266.05
CPO-Kandla (M)	10 K	794.80	804.90
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	778.95	782.90
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	800.00	790.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	906.15	906.15
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1550.35	1550.35
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3451.50	3450.30
Gold Ahm (M)	10 G	39851.00	39912.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32009.00	32058.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4001.00	4008.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7338.90	7355.55
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4034.70	4042.80
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4025.00	4025.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1130.10	1130.05
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	104.80	104.85
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16000.00	16250.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15800.00	15587.50
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	900.00	895.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1050.30	1045.85
Kapas-Rajkot (N)	X	1058.00	1052.45
Lead Mum (M)	1 K	153.30	154.80
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1965.00	1965.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2309.50	2285.00
Maize-Erode (N)	X	1950.00	1950.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2180.00	2170.00
Maize-Sangli (N)	X	1956.55	1935.40
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4912.50	4925.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7711.10	7722.20
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4449.90	4437.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	1036.00	1038.20
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3270.00	3270.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	339.40	337.80
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34045.45	33966.65
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	885.00	876.25
Rape mustards-Patan (I)	20 K	778.00	787.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1936.10	1917.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5270.65	5325.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	871.25	868.75
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	908.40	900.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	897.70	899.25
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	921.50	913.75
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13800.00	13700.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13800.00	13708.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46425.00	46070.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4363.00	4309.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4242.00	4242.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4393.50	4307.65
Soy Bean-Akola (N)	X	4293.00	4246.00
Soymeal Indore (N)	1 T	34700.00	34500.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	910.40	902.50
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32000.00	31490.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31700.00	31500.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28870.00	28480.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3275.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3419.05	3380.50
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3315.00	3300.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3466.65	3447.60
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3306.90	3300.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3172.50	3163.15
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6077.50	6077.50
Wheat Delhi (N)	1 Q	2207.50	2200.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2180.85	2181.90
Wheat New Indore (N)	1 Q	2212.50	2205.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2095.00	2080.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2250.00	2235.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5600.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5775.00	5825.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	186.90	189.40

* as on Jan 21, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (बुधवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19650, 19670, 19450, 19570	6237	921	15672
Feb 28	19850, 19940, 19730, 19870	6926	907	15893
Mar 31	20070, 20190, 20040, 20160	918	127	2211
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	2002, 2030, 1974, 2022	55720	3708	88530
Mar 20	2034, 2057, 2002, 2048	15880	1315	20960
Apr 20	2043, 2082, 2030, 2076	3530	283	8850
May 20	2071, 2107, 2057, 2089	370	33	820
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1103, 1111, 1100, 1109.5	256	39	972
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1102, 1111.5, 1099, 1111	1722	900	4250
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4108, 4134, 4088, 4122	23020	2763	88365
Mar 20	4142, 4174, 4134, 4168	4825	720	7745
Apr 20	4194, 4198, 4186, 4186	55	11	85
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4168, 4168, 4088, 4102	5410	665	24705
Mar 20	4150, 4150, 4092, 4108	1630	224	9365
Apr 20	4152, 4152, 4128, 4146	1225	98	3275
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	783.1, 797.9, 778.4, 795.9	18150	1388	34220
Feb 28	780.1, 788, 771.7, 786.2	25360	1507	46310
Mar 31	775.2, 780.4, 765.1, 777.8	2430	155	9040
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1234.5, 1235.7, 1223.1, 1229.5	120.6	249	176.76
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46075, 46325, 45937, 46263	85.57	13433	57.29
Apr 30	46533, 46809, 46528, 46778	1.72	325	4.55
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Jan 28	134.9, 136.6, 134.9, 136.3	46973mb	21124	36366mb
Feb 25	135.5, 136.9, 135.5, 136.6	6429mb	3476	28889mb
Mar 26	138.7, 139.8, 138.7, 139.7	373mb	238	2999mb
Oil				
Crude Oil MCX(7 BL)				
Feb 19	4171, 4171, 4128, 4143	8269bl	50893	2820bl
Mar 19	4160, 4160, 4136, 4151	151bl	1326	87bl
सायं सत्र (मंगलवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19710, 19710, 19570, 19600	3682	689	16611
Feb 28	19970, 19970, 19850, 19860	2793	487	13342
Mar 31	20210, 20210, 20130, 20140	166	26	1807
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1125, 1125, 1103, 1105.5	740	120	856
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1125, 1126, 1103, 1105.5	2244	1303	4449
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	799.3, 801.6, 784.4, 787.3	18170	1424	33540
Feb 28	794, 794.7, 778.7, 781.1	21830	1416	43230
Mar 31	780.1, 788, 772.8, 774	2550	163	8870
Apr 30	767, 767, 766.8, 766.9	20	2	210
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	892.8, 892.8, 876.4, 880.4	31355	3605	55920
Mar 20	885.4, 885.4, 862, 869.6	11140	1268	27460
Apr 20	872, 874.2, 860.4, 868.6	860	152	3370
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	142.25, 143.45, 142.25, 142.85	4	4	2
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	141.05, 142.25, 140.65, 142.05	8817	5829	3878
Feb 28	142, 142.35, 141.4, 142.2	1298	916	1858
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	454.25, 454.25, 450.2, 452.55	23367.5	8190	10002.5
Feb 28	454, 454, 450.25, 451.05	3075	950	4835
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	150.85, 151.95, 150.5, 151.75	13108	7871	3858
Feb 28	152.3, 152.3, 151.5, 152.25	2067	1410	1989
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	1028, 1034, 1012.3, 1015.5	29790	18325	2184
Feb 28	1009, 1018.5, 1001.8, 1003.5	1735.5	1092	1213.5
Mar 31	1010, 1010, 1001.5, 1006	6	4	16.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	186.75, 188.8, 185.25, 186.4	13	13	3
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	182.05, 184.45, 181.25, 184.25	40024	22715	10165
Feb 28	183.5, 185.6, 182.65, 185.45	6612	3999	9227
Mar 31	184.85, 185.7, 184, 185.6	51	27	49
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40090, 40176, 39675, 39911	14.86	12606	10.15
Apr 03	40100, 40290, 39785, 40031	1.64	1301	12.27
Jun 05	40386, 40393, 39946, 40079	0.15	123	0.6
Gold Guinea MCX(8 G)				
Jan 31	31949, 31979

सीएए: केंद्र को सुने बिना रोक नहीं

शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार का पक्ष सुनना जरूरी

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को साफ कर दिया कि वह केंद्र की दलीलों को सुने बगैर नागरिकता कानून (सीएए) पर रोक नहीं लगाएगा। अदालत ने कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की वैधता का फैसला करेगा। शीर्ष अदालत ने सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इसने उच्च न्यायालयों को भी इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं पर सुनवाई रोकने का निर्देश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाला पीठ सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली 143 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी शामिल हैं।

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि 143 याचिकाओं में से करीब 60 की प्रतियां सरकार को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सरकार को समय चाहिए, जो उसे अभी नहीं मिल पाई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से सीएए को लागू करने पर रोक लगाने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की कवायद फिलहाल टाल देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले पर केंद्र को सुने बगैर सीएए पर कोई रोक नहीं लगाएगा।

सीएए में 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे उसने कानून की शक्ल ले ली।

आईयूएमएल ने अपनी याचिका में कहा कि सीएए बराबरी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और इसका मकसद धर्म के आधार पर लोगों को बाहर कर अवैध शरणार्थियों के एक वर्ग को नागरिकता देना है।

> उच्च न्यायालयों को भी इस कानून पर लंबित याचिकाओं पर सुनवाई रोकने का निर्देश दिया गया है

ममता का विरोध

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएए की धाराओं पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने केंद्र पर इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। दार्जिलिंग में सीएए के खिलाफ चार किलोमीटर लंबे विरोध मार्च का नेतृत्व करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि केंद्र सरकार केवल गैर-भाजपा शासित राज्यों में सीएए को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के भय से पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य नई दिल्ली में एनपीआर को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने दोहराया कि राज्य में सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बसपा बहस को तैयार

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर बहस करने की सत्तापक्ष की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी इन मुद्दों पर किसी भी मंच पर बहस करने को तैयार है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, 'अति-विवादित सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ पूरे देश में खासकर युवा व महिलाओं के संगठित होकर संघर्ष करने और आंदोलित होने से परेशान केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ की रैली में विपक्ष को इस मुद्दे पर बहस करने की चुनौती को बसपा किसी भी मंच पर और कहीं भी स्वीकार करने को तैयार है।'

कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर का विरोध करती महिलाएं (पीटीआई)

बढ़ते पेच

- नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को चार हफ्ते में देना है जवाब
- इस मामले की सुनवाई पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगी
- सीएए, एनआरसी के विरोध में दार्जिलिंग में ममता बनर्जी की बड़ी रैली

मुस्लिम लीग कांग्रेस

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर 'मुस्लिमों के तुष्टिकरण' और हिंदुओं के 'अपमान' का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि विपक्षी पार्टी को 'मुस्लिम लीग कांग्रेस' कहा जाना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने चव्हाण के इस कथित बयान का हवाला दिया कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिव सेना के साथ हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि पार्टी भाजपा को सत्ता में आने से रोके। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भाजपा को 'नाथूराम गोडसे पार्टी','भ्रष्ट जुमला पार्टी' और 'बिकाऊ जनता पार्टी' करार दिया। *एजेंसियां*

चीन में कोरोना वायरस से महामारी की आशंका गहरी

रॉयटर्स

चीन में कोरोना फ्लू से मरने वाले लोगों की संख्या बुधवार को बढ़कर 9 पर पहुंच गई। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 440 लोग इस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और प्रशासन ने हुबेई प्रांत में लोगों की भीड़ एकत्रित न होने देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। जहां चीन ने अस्पतालों में रोकथाम संबंधी उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह पता लगाने के लिए एक आपात बैठक आयोजित की कि क्या नए कोरोना वायरस का प्रकोप वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बन सकता है। हुबेई के वुहान शहर में पिछले साल के अंत में इस वायरस का मामला सामने आया था और उसके बाद से यह पेइचिंग, शांघाई और मकाउ समेत चीन के कई शहरों के साथ साथ अमेरिका, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में फैल चुका है।

चीन सरकार ने इस बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इस संक्रमण के मामलों की संख्या के बारे में दैनिक जानकारी मुहैया कराई है, क्योंकि लाखों लोग लूनर नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।

नैशनल हेल्थ कमीशन के उप-मंत्री ली बिन ने पत्रकारों को बताया, 'लोगों की गतिशीलता में वृद्धि से इस महामारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है और इससे इसकी रोकथाम और नियंत्रण में समस्या पैदा हो रही है।'

ली ने कहा कि यह पता चला है कि वायरस सांस के जरिये शरीर में प्रवेश कर रहा है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रीवेंशन के महानिदेशक गाउ फू ने कहा कि वायरस के तेजी से फैलने की वजह से स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चुनौती पैदा हो गई है।

संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लगभग 2,197 लोगों को अलग रखा गया था, जबकि 765 को जांच से मुक्त कर दिया गया है।

ली ने कहा, 'मामलों की संख्या में बड़ा बदलाव बीमारी के बारे में हमारी बढ़ती समझ, जांच प्रणालियों में सुधार और जांच किटों के वितरण आदि की वजह से आया है।'

इस वायरस के लक्षणों में बुखार आना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ मुख्य रूप से शामिल हैं। यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है, और चीन में 15 चिकित्साकर्मी भी इससे ग्रसित हो चुके हैं। इस महामारी की आशंका चीन में 2002-2003 में फैली सेवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (एसएआरएस) महामारी के समान है जिसमें लगभग 800 लोग मारे गए थे। इस महामारी से वैश्विक बाजार प्रभावित हुए थे। विमानन और लक्जरी उत्पाद कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखा गया था और चीन की मुद्रा युआन में बड़ी कमजोरी आ गई थी।

ऐपल की आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन के अरबपति संस्थापक टेरी गोउ ने कहा कि इस वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वह कंपनी के कर्मचारियों को छुट्टियों के दौरान चीन की यात्रा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता तारिक जासारेविक ने कहा कि कोरोना वायरस के नए मामले दिख सकते हैं क्योंकि चीन ने इसकी निगरानी प्रक्रिया तेज की है।

हालांकि अभी इसका पता नहीं लगाया जा सका है कि यह वायरस कहां से आया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इसका प्रमुख स्रोत शायद पशु हो सकता है। चीन के अधिकारियों ने इस महामारी का संबंध वुहान के समुद्री खाद्य बाजार से होने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया और ताईवान ने अपने नागरिकों को वुहान की यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी है। ताईवान ने मंगलवार को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की। यह संक्रमण वुहान से ताइवान लौटी महिला में पाया गया।

हॉन्गकॉन्ग की ट्रेन में वायरस से बचाव के लिए मास्क पहने बच्चे

जांच में वायरस का मामला नहीं

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बुधवार को बताया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत 7 हवाई अड्डों पर मंगलवार तक कुल 43 उड़ानों और 9,156 यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए जांच की गई। हालांकि अभी तक जांच में कोई मामला सामने नहीं आया है। सूदन ने बताया कि चीन में भारतीय दूतावास उस देश में संक्रमित मामलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को नियमित रूप से जानकारी दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाले यात्रियों की हवाईअड्डों पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। पिछले कुछ समय में चीन से भारत आने वालों से भी कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती लक्षण पाए जाने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराने का अनुरोध किया जा रहा है।

- चीन में **440** लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, **9** लोगों की मौत हुई है
- डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इस तरह के संक्रमण के और मामले सामने आ सकते हैं
- यात्रा न करने की चेतावनी जारी, उत्तर कोरिया ने विदेशी पर्यटकों की यात्रा को प्रतिबंधित किया

सहयोगी कंपनियों के साथ से गूगल आगे

गूगल के सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी कंपनी बनने के जोखिम को खारिज करते हुए कंपनी के मुख्य कार्यकारीअधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने बुधवार को कहा कि गूगल तभी अच्छा कर पाएगी जब उसके साथ अन्य कंपनियां भी बेहतर करेंगी। पिचाई दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। पिचाई ने कहा, 'जिस स्तर पर आज कंपनी है उसका निगरानी में आना स्वभाविक है। हमने स्टार्टअप कंपनियों को खरीदा है लेकिन अपनी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से हम हर साल सैकड़ों स्टार्टअप में निवेश भी कर रहे हैं।'

पिचाई ने कहा कि दुनिया को सभी लोगों के लिए एक मुक्त और स्वतंत्र इंटरनेट प्रणाली की जरूरत है। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के लिए एक साझा नियमन प्रणाली बनाने के लिए सभी देश मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि निजता कोई विलासिता की वस्तु नहीं हो सकती और इसे हर किसी के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए। पिचाई ने कहा, 'हमें सबके लिए एक स्वतंत्र और मुक्त इंटरनेट चाहिए। डेटा की संप्रुभता हर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और दुनिया के किसी भी हिस्से में डेटा की सुरक्षा व्यवस्था तय करते समय इस पर गौर करने की जरूरत है।'

गोयल की निवेश पर चर्चा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यू यंग-ही के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने दावोस में बैठक के दौरान कई उद्योगपतियों और विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। गोयल ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया के मंत्री के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने से जुड़े भारत की चिंताओं को उठाया। गोयल ने यहां उद्योगपतियों के साथ गोलमेज बैठक में भारतीय रेलवे में निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।

पासवर्ड की चोरी

दुनियाभर में साइबर अपराध और डेटा चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच एक अध्ययन में दावा किया गया है कि इसकी बड़ी वजह पासवर्ड चोरी हो जाना या कमजोर पासवर्ड होना है। किसी व्यक्ति का पासवर्ड से मुक्त होना उसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी 2020 की सालाना बैठक के दौरान यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेटा चोरी की पांच घटनाओं में से चार का कारण पासवर्ड का कमजोर होना या उसका चोरी हो जाना होता है। बड़ी कंपनियों के आईटी हेल्प डेस्क की करीब 50 प्रतिशत लागत सिर्फ पासवर्ड के दोबारा आवंटन पर लगती है। 2020 में करीब 80 फीसदी साइबर हमले पासवर्ड से जुड़े होंगे। *एजेंसियां*

विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (पीटीआई)

कश्मीर: मध्यस्थता की संभावना नहीं

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद की अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नई पेशकश के जवाब में सरकार के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की किसी भी भूमिका की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत का लंबे समय से रुख रहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है तथा किसी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता या हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ट्रंप ने मंगलवार को दावोस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे से जुड़े घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। उन्होंने इस विवाद को सुलझाने में मदद की पेशकश दोहराई। पिछले पांच महीने में ट्रंप की ओर से कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देशों की मदद की यह चौथी पेशकश है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति फरवरी में भारत का दौरा कर सकते हैं।

गुजराती झांकी का जलवा

फोटो: संजय शर्मा

गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए आई गुजरात राज्य की झांकी के साथ बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी नजर आए। पंकज मोदी गुजरात के सूचना विभाग में अधिकारी हैं

कारोबारी वजहों से आत्महत्या करने की बढ़ी तादाद

सचिन मामबटा

अगर बॉलीवुड की मशहूर हस्ती अमिताभ बच्चन अपने मुश्किल दिनों में किसी से मदद मांग सकते हैं तो दूसरे लोगों को भी ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुंबई के मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि मुश्किल वक्त में मदद मांगने से गुरेज नहीं होना चाहिए। अमिताभ भी जब आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजर रहे थे तब उन्होंने यश चोपड़ा से अपनी फिल्म में कोई भूमिका देने की गुजारिश की थी। मनोरोग चिकित्सकों द्वारा यह सलाह देने की कुछ अहम वजहें भी हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरुकता का अभाव और समाज में निंदा के डर से कारोबारी लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने की तादाद में वर्ष 2018 में बढ़ोतरी हुई जबकि इससे पिछले दो सालों में आत्महत्या की तादाद में कमी आई थी।

नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के सरकारी डेटा के मुताबिक वर्ष 2018 में कुल 7990 कारोबारी लोगों ने आत्महत्या कर ली जो इससे पिछले साल के 7778 लोगों की आत्महत्या के मुकाबले 2.7 फीसदी अधिक था। आत्महत्या करने वाले लोगों के पेशे का जायजा लेने पर यह डेटा सामने आया है।

कर्नाटक में सबसे ज्यादा 1,113 ऐसे मामले सामने आए। इसके बाद महाराष्ट्र (969) और तमिलनाडु (931) का स्थान है। ये राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से उच्च पायदान पर है लेकिन लोगों को कड़ी मेहनत के बावजूद अपने कारोबार से मुनाफा पाना मुश्किल साबित हो रहा है। मानसिक रोग की डॉक्टर और लेखक अंजलि छाबड़िया कहती हैं, 'अब अचानक लोगों को यह महसूस होने लगा है कि अगर आप पूरे दिन भी कड़ी मेहनत करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पैसे कमा लेंगे। कई दफा लोग उन वजहों से भी शर्मिंदा हो जाते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं जो उनके वश में नहीं है।'

एनसीआरबी के आंकड़े भी आत्महत्या की वजहों का जिक्र करते हैं। दिवालिया होने या कर्ज में फंसने की वजह से करीब 4970 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2018 में देश भर में आत्महत्या करने वाले लोगों में कारोबारी लोगों की तादाद 3.7 फीसदी तक रही। हैरानी की बात यह है कि यह इससे पहले के साल में हुई 5151 आत्महत्याओं के मुकाबले कम था। 2017 में कुल आत्महत्या की घटनाओं में कारोबारी लोगों द्वारा की गई आत्महत्या की तादाद 4 फीसदी तक थी।

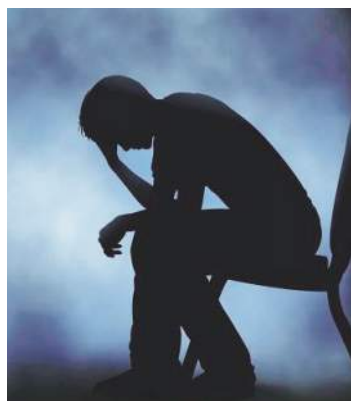

मुंबई के मनोचिकित्सक हरीश शेट्टी का कहना है कि यह आंकड़ा कम करके बताया जा सकता है। कई मामलों में दिवालिया होने की बात पता भी नहीं चलती है और ऐसे मामलों को आमतौर पर पारिवारिक वजह बता दिया जाता है। इसकी वजह यह भी है कि कारोबार में नाकाम होने की बात को शर्मिंदगी के तौर पर देखा जाता है। वह कहते हैं, 'कारोबारी नुकसान को कलंक के तौर पर देखा जाता है और इस बात को कोई परिवार आसानी से किसी से साझा नहीं करता है।' ऐसे ज्यादातर मामले में इसकी वजह पारिवारिक बता दी जाती है। ऐसी घटनाओं की तादाद 2017 के 30.1 फीसदी से बढ़कर 2018 में 30.4 फीसदी हो गई। हरीश शेट्टी कहते हैं कि पारिवारिक तनाव की स्थिति भी आर्थिक दबाव की वजह से बनती है। वर्ष 2018 में आत्महत्या की घटनाओं में बीमारी से जुड़ी आत्महत्या की तादाद 17.7 फीसदी तक रही। वहीं शादी से जुड़ी समस्याओं की वजह से ऐसी आत्महत्या की तादाद 6.2 फीसदी तक रही। वहीं कुल आत्महत्या में ड्रग और नशे की लत की वजह से आत्महत्या करने की तादाद 5.3 फीसदी रही।

2018 में आत्महत्या में कमी आई लेकिन दिवालिया होने की वजह से रोजाना आत्महत्या की 13 से अधिक घटनाएं हुईं। आत्महत्या की घटनाओं पर पेशे के आधार पर गौर किया जाए तो यह अंदाजा होगा कि कारोबारी लोग रोजाना 21 की दर से आत्महत्या करते हैं। केवल महाराष्ट्र में ही दिवालिया होने की वजह से 1541 लोगों ने आत्महत्या की और ऐसी घटनाओं के लिहाज से महाराष्ट्र अन्य राज्यों के मुकाबले आगे है। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है जहां 1391 लोगों ने कारोबार की वजह से आत्महत्या कर ली। अगर शहर के लिहाज से जायजा लिया जाए तो बेंगलूरु में 142 लोगों ने दिवालिया होने की वजह से आत्महत्या कर ली। जबकि 2018 में मुंबई में केवल 20 लोगों ने ही कारोबारी वजहों से आत्महत्या की।

जलवायु परिवर्तन पर चिंतित उद्योग जगत

पृष्ठ-1 का शेष

श्लोका कहती हैं, 'आईसीसी इन निवेशकों को सरकारी एजेंसियों, अकादमिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के व्यापक नेटवर्क से जोड़ेगा। अभी ये सब अलग-अलग काम करते हैं।' इसका मकसद यह है कि कंपनियां भविष्य को सुरक्षित रखने के लिहाज से अपनी योजनाएं बना सकें।

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने जलवायु संकट से निपटने में अगले दशक को अहम बताते हुए कहा, 'दुनिया चलताऊ तरीके से नहीं चलती रह सकती है और कोई भी व्यक्ति अपने दम पर इसे नहीं दूर कर सकता है। इसके लिए कारोबार जगत, सरकार और परोपकारी लोगों को साथ आना होगा ताकि बड़े पैमाने पर और जल्द नतीजे मिल सकें। आईसीसी यह काम कर सकता है।'आईसीसी के गठन का विचार सबसे पहले 2018 में ही आया था। उसके बाद से इसकी रूपरेखा बनाने का काम शुरू हुआ और अब यह अस्तित्व में आ चुका है। इस समय इसके 45 से अधिक सदस्य हैं। इनमें भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार, द एनर्जी ऐंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी), अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च ऑन इकोलॉजी ऐंड एनवायरमेंट, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरमेंट, महिंद्रा ग्रुप, विप्रो, गोदरेज इंडस्ट्रीज और एचयूएल फाउंडेशन भी शामिल हैं।आईसीसी के बैनर तले पहला कार्यक्रम वायु गुणवत्ता को लेकर चलाया जाएगा। यह आगे चलकर पानी एवं जमीन मामलों से जुड़ी पहल भी लेकर आएगा।